बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 99

नई शुरुआत

नीतिगत निर्णय ले सकने में मदद करने वाले कई आर्थिक संकेतकों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि इस समाचार पत्र में तथा अन्य जगहों पर भी प्रकाशित हुआ, केंद्र सरकार का सांख्यिकी विभाग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए नई श्रृंखलाओं पर काम कर रहा है।

ये अगले वर्ष जारी की जा सकती हैं। भारत जैसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि प्रमुख संकेतकों को नियमित रूप से संशोधित किया जाए और समायोजित भी किया जाए। हाल के वर्षों के दौरान संशोधन में देरी हुई। ऐसा आंशिक रूप से कोविड के कारण हुआ और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों के बीच लंबे अंतराल की वजह से भी हुआ। जैसा कि इस समाचार पत्र में बुधवार को प्रकाशित भी हुआ, सरकार अब यह योजना बना रही है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों को निरंतर और कम अंतराल पर अंजाम दिया जाए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मौजूदा जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है। संदर्भ के लिए बताते चलें कि डॉलर के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2025 तक बढ़कर 2011 के आकार के 2.3 गुना तक हो जाने का अनुमान है। पिछले संशोधन के बाद से भारत में काफी बदलाव हो चुका है और यह संभव है कि मुख्य संकेतक अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर नहीं पेश कर पा रहे हों।

अनुमानित संशोधन न केवल आधार वर्ष को बदल देगा बल्कि नए डेटा स्रोत भी शामिल करेगा जिनकी बदौलत इन संकेतकों में और अधिक मजबूती आनी चाहिए। उदाहरण के लिए नया सीपीआई करीब 2,900 भौतिक बाजारों के मूल्य संबंधी आंकड़ों को दर्शाएगा जबकि मौजूदा श्रृंखला में 2,300 बाजार शामिल हैं। यही नहीं, विभाग 12 शहरों से ऑनलाइन डेटा भी जुटाएगा ताकि ई-कॉमर्स क्षेत्र में आ रहे बदलाव को दर्ज किया जा सके। यह सही है कि अब ई-कॉमर्स शहरी भारत में महत्त्वपूर्ण पहुंच रखता है लेकिन ग्रामीण भारत के कुछ इलाकों में भी इसकी अच्छी खासी पहुंच है। देश का शहरीकरण हो रहा है और ऐसे में उपभोक्ताओं द्वारा इसे अपनाया जाना बढ़ेगा। इस वर्ष के आरंभ में जानकारी आई थी कि सरकार एक अलग ई-कॉमर्स सूचकांक की संभावनाओं का आकलन कर रही है जो घरेलू खपत पर इस माध्यम से भी नजर रखेगा। ऐसे सूचकांकों का निर्माण करना सही रहेगा। गहराई और दायरे के आधार पर यह महत्त्वपूर्ण सूचनाएं मुहैया कराएगा, मसलन खपत का रुझान और मांग में परिवर्तन। वास्तव में ई-कॉमर्स क्षेत्र पर करीबी नजर रखने से जीडीपी आंकड़ों को समृद्ध बनाने में मदद मिल सकती है। ऐसे सूचकांकों को मासिक स्तर पर जारी करना अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम संकेतक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, जैसा कि रिपोर्ट बताती हैं, नई सीरीज में जीडीपी के अनुमानों में वस्तु एवं सेवा कर के आंकड़े तथा नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। आधार वर्ष में पिछले संशोधन के समय ये स्रोत उपलब्ध नहीं थे। सटीक आंकड़े नीति निर्माण और निजी क्षेत्र के लिए निर्णय लेने, दोनों ही मामलों में उपयोगी साबित होते हैं। उदाहरण के लिए ताजा खपत आंकड़ों के अनुसार अर्थशास्त्र के कुछ विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि सीपीआई में खाद्य उत्पादों का भार काफी कम हो सकता है। फूड बास्केट के घटकों में भी शायद बदलाव आ गया है और खराब होने वाले उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। ये सभी बातें हेडलाइन मुद्रास्फीति को अलग-अलग तरह से प्रभावित करेंगी और मौद्रिक नीति पर इसका असर होगा। मुद्रास्फीति को लक्षित बनाने के ढांचे को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए यह अहम है कि वास्तविक स्थिति की जानकारी हो।

बहरहाल आगामी संशोधन इस तथ्य से प्रभावित हो सकते हैं कि सर्वेक्षण के आंकड़े अभी भी उन नमूनों पर आधारित हैं जो 2011 की जनगणना के हैं। जीडीपी के आंकड़ों के संदर्भ में सांख्यिकी विभाग को मौजूदा श्रृंखला की आलोचना को दूर करने का लक्ष्य भी लेकर चलना चाहिए। ऐसी ही एक आलोचना नॉमिनल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में बदलने की भी है। इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने लायक है कि भारत को एक उत्पादक मूल्य सूचकांक की भी आवश्यकता है ताकि ऐसे मसलों को हल किया जा सके। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि इस प्रकार का सूचकांक विचाराधीन है लेकिन यह तय नहीं है कि यह कब तक बनेगा और क्या इसमें नई श्रृंखला का इस्तेमाल किया जाएगा?

विनय सिन्हा

राजस्व के अधिक अनुमान के खतरे

राजकोषीय अनुशासन से तात्पर्य केवल घाटे के लक्ष्यों को पूरा करना भर नहीं है, बल्कि इसका संबंध व्यय, राजस्व संग्रह आदि के मोर्चे पर सटीक अनुमान लगाने से भी है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

क्या 2024-25 के केंद्रीय बजट के लिए हाल ही में जारी किए गए प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों में 'देजा वू' की भावना है? देजा वू एक ऐसी स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह किसी घटना को पहले भी अनुभव कर चुका है, भले ही वह पहली बार घटित हो रही हो। ये आंकड़े गत माह के अंत में सार्वजनिक किए गए। इन प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों की अगर 2024-25 के संशोधित अनुमानों से तुलना की जाए तो पता चलता है कि राजस्व के बढ़-चढ़े अनुमानों की समस्या दोबारा सिर उठा चुकी है। ऐसा चार वर्ष के अंतराल के बाद हुआ है।

किसी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट के संशोधित अनुमान वर्ष के समापन के करीब दो माह पहले जारी किए जाते हैं। यह प्रायः अगले वर्ष के बजट की प्रस्तुति से टकराते हैं। इस तरह 2024-25 के बजट के संशोधित अनुमान 1 फरवरी, 2025 को उपलब्ध हुए जिस दिन 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। हालांकि संशोधित अनुमान उस वर्ष के लिए एक अनुमान होता है लेकिन इसके और उन प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों के बीच अधिक अंतर नहीं होना चाहिए जो उस वर्ष मई के अंत में उपलब्ध होते हैं। आदर्श स्थिति में राजस्व संग्रह का बढ़ाचढ़ाकर अनुमान लगाने से बचना चाहिए। ठीक इसी तरह, व्यय का सही अनुमान न लगाना सरकारी वित्त के प्रबंधन में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है।

निर्मला सीतारमण ने बीते छह वर्षों में जो बजट पेश किए उनमें 2019-20 के बजट में राजस्व का अधिक आकलन करना एक बड़ी समस्या थी, जो उनका पहला बजट भी था। इस समस्या के आकार की बात करें तो वह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन इसने उनके पहले बजट को दिक्कत में डाला। ऐसे में वास्तविक विशुद्ध कर राजस्व संग्रह की बात करें तो 2019-20 में (जब कोविड लॉकडाउन की घोषणा मार्च 2020 के तीसरे सप्ताह में की गई थी) यह संशोधित अनुमान की तुलना में 13.6 फीसदी कम निकला। गैर कर राजस्व में भी संशोधित अनुमान से 5 फीसदी की कमी आई और व्यय में केवल मामूली बदलाव आया। इस तरह 2019-20 में वास्तविक राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.6 फीसदी हो गया जबकि संशोधित अनुमान में इसके 3.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। कोविड भी एक कारक रहा है लेकिन वित्त मंत्रालय की राजस्व का अधिक अनुमान लगाने की प्रवृत्ति भी इस भारी अंतर के लिए समान रूप से जिम्मेदार रही है।

अगले चार वर्षों तक सीतारमण और वित्त मंत्रालय की उनकी टीम ने संशोधित अनुमान जताने में अत्यधिक सावधानी बरती। राजस्व के अधिक अनुमान की दिक्कत के बजाय राजस्व का कम अनुमान लगाया जाने लगा। इन चार सालों में यानी 2020-21 से 2023-24 के बीच वास्तविक आंकड़े पहले जारी संशोधित अनुमान की तुलना में अधिक रहे। इस अवधि के दौरान विशुद्ध कर राजस्व में इजाफे का दायरा 0.13 फीसदी से करीब 6 फीसदी तक अधिक रहा। व्यय के मोटे तौर पर नियंत्रण में रहने के बीच वास्तविक राजकोषीय घाटा इन चार सालों में संशोधित अनुमान से कम रहा।

गत माह के आंकड़ों ने बताया कि यह रुझान अब बदल गया है। 2024-25 में शुद्ध कर राजस्व के लिए प्रारंभिक वास्तविक आंकड़े संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.3 फीसदी कम हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा बदलाव व्यक्तिगत आय कर संग्रह में नजर आया जहां प्रारंभिक वास्तविक आंकड़े 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 6 फीसदी कम रहे। बीते छह साल में व्यक्तिगत आय कर प्राप्तियों की सकल कर राजस्व में हिस्सेदारी करीब एक चौथाई से बढ़कर एक तिहाई हो गई। महज चार महीनों में व्यक्तिगत आय कर संग्रह को संशोधित करके 74,000 करोड़ रुपये तक कम करना पड़ा जो चिंता का विषय है और इसकी वजह की जांच की जानी चाहिए। क्या इसमें ऐसा कोई संदेश छिपा है कि जिससे सरकार चालू वर्ष में व्यक्तिगत आय कर संग्रह को लेकर कोई रुझान देख सकती है। वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्तिगत आय कर संग्रह में तेज गिरावट ही शायद वह प्रमुख वजह थी जिसके चलते सरकार ने राजस्व व्यय पर लगाम लगाई। वर्ष2024-25 के 37.1 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय का संशोधित अनुमान 36.98 लाख करोड़ रुपये रहा। चार महीने बाद इसके प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों को 36.03 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

इन बदलावों में इकलौती उम्मीद की किरण है व्यय की गुणवत्ता में सुधार। पूंजीगत व्यय के प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों में इजाफा नजर आया जबकि राजस्व व्यय के मामले में यह कम रहा। अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का सांकेतिक आकार इस अवधि में बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप घाटा जीडीपी के 4.8 फीसदी पर रहा।

वित्त मंत्रालय को संशोधित अनुमान और प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों के बीच के अंतर को न्यूनतम क्यों रखना चाहिए? असल में, यह न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में भ्रामक संकेत देता है, बल्कि भारी अंतर केंद्रीय मंत्रालयों को मजबूर करते हैं कि वे अवांछित विकल्पों की ओर जाएं। चूंकि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करके एक खास स्तर तक लाने को प्रतिबद्ध है इसलिए राजस्व के आंकड़ों को संशोधित अनुमानों में बढ़ाचढ़ाकर पेश करना, केंद्रीय मंत्रालयों को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वे साल के आखिरी महीनों में अपने व्यय में कटौती करें ताकि घाटा लक्ष्य के करीब बने रहें। आखिरी मिनट की ऐसी व्यय कटौती अक्सर राजकोष को अस्वास्थ्यकर नतीजों की ओर ले जाती है। इससे काल्पनिक व्यय बजट की स्थिति भी बन सकती है जिसके नतीजतन व्यय संबंधी देनदारियों को राज्य के स्वामित्व वाली इकाइयों को हस्तांतरित किया जा सकता है या बजट से बाहर उधारी का सहारा लिया जा सकता है, जबकि यह चलन कुछ साल पहले समाप्त हो चुका था।

राजस्व के अधिक अनुमान का करीबी परीक्षण करने की एक और वजह है। वास्तविक आंकड़ों का संशोधित अनुमान से कम रह जाना आर्थिक गतिविधियों की गति में कमजोरी का भी आरंभिक संकेत है। वर्ष 2019-20 में राजस्व के अधिक अनुमान इस बात के संकेत थे कि आर्थिक गतिविधियों में धीमापन आ रहा है। इसी प्रकार 2020-21 से 2023-24 तक चार साल के दौरान संशोधित अनुमानों में राजस्व अनुमानों का कम रहना जीडीपी वृद्धि की गति में चरणबद्ध तरीके से सुधार के साथ हुआ।

वर्ष 2024-25 में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.5 फीसदी रह गई जबकि 2023-24 में वह 9.2 फीसदी थी। 2024-25 में राजस्व को बढ़ाचढ़ा कर पेश करने की समस्या के दोबारा सामने आने को अर्थव्यवस्था में वृद्धि की कमजोर पड़ती गति का संकेत माना जा सकता है। 2024-25 के संशोधित अनुमान में उल्लिखित आंकड़ों की तुलना में व्यक्तिगत आय कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए अंतिम वास्तविक राजस्व संग्रह में कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने वालों के लिए एक चेतावनी की तरह होना चाहिए।

बाहरी अनिश्चितताओं में इजाफे के बीच देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के समक्ष चुनौतियां और मजबूत होती जाएंगी। इतना ही नहीं, राजकोषीय अनुशासन का संबंध न केवल घाटे के लक्ष्य को हासिल करने से है बल्कि राजस्व और व्यय के सटीक अनुमानों से भी उसका ताल्लुक है। ऐसे में अब सरकार को संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व संग्रह में आई कमी के कारणों की जांच पर ध्यान देना चाहिए।

अमेरिका के बढ़ते ऋण का परिणाम

बाजार पूंजीकरण के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज के मुख्य कार्याधिकारी जेमी डिमन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि अमेरिकी बॉन्ड बाजार में दरार आकर रहेगी। निस्संदेह यह पूर्वानुमान गंभीर है और अगर यह सही साबित हुआ तो वित्तीय बाजारों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर होगा। अमेरिका का डेट बाजार दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे नकदीकृत सरकारी प्रतिभूतियों वाला डेट बाजार है। चूंकि वैश्विक वित्तीय बाजार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और परस्पर निर्भर भी हैं, इसलिए अमेरिकी डेट बाजार में किसी हलचल का असर व्यावहारिक रूप से दुनिया की हर वित्तीय परिसंपत्ति पर पड़ेगा। वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए इसके गहरे निहितार्थ होंगे।

30 वर्ष के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर यील्ड हाल ही में 5 फीसदी के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई। 10 वर्ष के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यील्ड में भी तेजी आई जो यह रेखांकित करता है कि निवेशक अब जोखिम में कथित वृद्धि के कारण अमेरिकी सरकारी बॉन्डों को रखने पर उच्च प्रतिफल की उम्मीद कर रहे हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में अमेरिकी डेट की रेटिंग घटा दी है। चूंकि अन्य दो प्रमुख रेटिंग एजेंसियां पहले ही ऐसा कर चुकी हैं इसलिए एक सदी में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऋण बाजार ट्रिपल-ए रेटिंग नहीं पा सका है।

निवेशकों में घबराहट बढ़ने की एक स्वाभाविक वजह है अमेरिकी सरकारी ऋण में इजाफा होने का अनुमान। डॉलर में गिरावट भी सवालों की वजह बन रही है। अनुमानों के मुताबिक प्रतिनिधि सभा से पारित बिल जिसे अब सीनेट की मंजूरी का इंतजार है, वह अन्य बातों के अलावा कर कटौती बढ़ाएगा। माना जा रहा है कि अकेले इसकी बदौलत अगले एक दशक में संघीय ऋण भंडार में 4 लाख करोड़ डॉलर जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बजट ऑफिस के विस्तारित आधारभूत अनुमानों के मुताबिक जनता के पास मौजूद संघीय डेट भंडार के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष2025 के जीडीपी के करीब 100 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2055 तक 156 फीसदी हो जाने का अनुमान है। धीमी आर्थिक वृद्धि की बदौलत डेट में तेजी से इजाफा होगा। अमेरिकी बजट घाटा भी ढांचागत रूप से काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका का बजट घाटा जीडीपी के 6 फीसदी से ऊपर है जबकि उसका पिछले 50 साल का औसत 3.8 फीसदी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में श्रम बाजार हालात के अनुकूल होने के बावजूद घाटे का स्तर बढ़ा हुआ है। डेट स्टॉक में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए व्यय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में जाएगा। विशुद्ध ब्याज भुगतान 2015 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.3 फीसदी से बढ़कर 2025 में अनुमानित 3.2 फीसदी हो गया है। आने वाले वर्षों में इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है और यह सकल घरेलू उत्पाद के 5 फीसदी से ऊपर होगा। अमेरिका के सरकारी वित्त के लिए ऐसे अनुमान के तीन संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला, बढ़ता ब्याज बोझ सरकारी खर्च की संरचना को बदल देगा और संभावित रूप से वृद्धि के परिणामों को प्रभावित करेगा। दूसरा, अमेरिकी सरकार द्वारा अपने बजट घाटे के वित्तपोषण के लिए धन की अधिक मांग निजी निवेश को बेकार कर देगी। यह पूंजी की लागत को बढ़ाएगा और ब्याज दरों को ज्यादातार लोगों के अनुमान से भी ज्यादा लंबे समय तक ऊंचा रखेगा। कुछ टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि कम ब्याज दरों का दौर खत्म हो गया है। व्यापार संबंधित अनिश्चितताएं और मुद्रास्फीति पर उच्च टैरिफ का प्रभाव भी फेडरल रिजर्व द्वारा नीति समायोजन के दायरे को सीमित कर देगा।

अर्थतंत्र
राजेश कुमार

इसका नतीजा यह होगा कि कम निवेश उत्पादकता पर असर डालेगा और अमेरिका की दीर्घकालिक वृद्धि संभावनाओं को सीमित करेगा। यह वैश्विक वृद्धि की संभावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। तीसरा, अमेरिकी सरकार की उच्च वित्त पोषण आवश्यकताएं और अनुमानित उच्च ब्याज दर वैश्विक हालात को सख्त बनाएगी और बाहरी वित्त पर निर्भर देशों के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। अन्य विकसित देशों में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। हालांकि निवेशक अमेरिकी बाजार को लेकर अधिक चिंतित हैं और उनके पास इसकी वजह भी है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी डेट बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 175 देशों पर हुए अध्ययन में दो तिहाई से अधिक देशों का डेट भंडार महामारी के पहले के स्तर से अधिक है। विकसित देशों में डेट स्टॉक का स्तर 2030 तक जीडीपी के 113.3 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है यानी 2019 के स्तर से करीब 10 फीसदी अधिक। इसी समान अवधि में अमेरिका में डेट स्टॉक के 20 फीसदी के लगभग बढ़ने का अनुमान है। बहरहाल, यह दलील देना मुश्किल है कि अनुमानित अमेरिकी सरकारी ऋण की स्थिति निवेशकों को निकट से मध्यम अवधि में ट्रेजरी को सामूहिक रूप से छोड़ने के लिए विवश करेगी। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत अधिक विकल्प बाकी नहीं हैं। हालांकि सरकारी बॉन्ड के निरंतर जारी होने से बाजार में तेजी बनी रहेगी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर बिक्री के कारण यील्ड में कभी-कभी तेज उछाल से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। भारत जैसा देश जिसे वृद्धि भी हासिल करनी है और जो अपने बचत-निवेश अंतराल की भरपाई के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर करता है, उसे धीमी वैश्विक वृद्धि और वित्तीय बाजार की उच्च अस्थिरता के लिए तैयार रहना होगा। इनमें मुद्रा बाजार भी शामिल है।

आपका पक्ष

विकसित राष्ट्र में विकसित कृषि की अवधारणा

लेख 'भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि की होगी अहम भूमिका' महत्त्वपूर्ण तथ्यों को जनमानस और सरकार के समक्ष रखता है। मूलतः कृषि संविधान के तहत राज्य सूची में है और केवल आवश्यक कानून बनाने के लिए केंद्र को अधिकार है। जब विकसित कृषि विकसित राष्ट्र का संबल है तो कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में होना आवश्यक है जिससे कि देश भर में विभिन्न जलवायु और सिंचाई की परिस्थितियों और देश के विभिन्न भागों में कृषि शोध एवं नवोन्मेष का लाभ संपूर्ण देश के किसानों को मिले। केंद्र और राज्य सरकारों में कृषि मंत्रालयों के साथ कृषि, वाणिज्य मंत्रालय को भी संबद्ध होना चाहिए जिससे देश भर की फसलों के उत्पादन के अनुसार कृषि उपजों के आयात एवं निर्यात पर निर्णय लिया जा सके और देश भर में अनाज के मूल्यों पर भी नियंत्रण रहे। किसी कृषि खाद पर किसी भी तरह से जीएसटी नहीं लगना चाहिए और किसानों द्वारा कृषि प्रसंस्करण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। छोटे स्तर पर हर गांव के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी आवश्यक है। जब तक किसान को कृषि शोध संस्थानों से जोड़ा नहीं जाएगा और स्कूली शिक्षा में कृषि एक विषय नहीं बनेगा, तब तक कृषि को सम्मान नहीं मिलेगा।

विनोद जौहरी, दिल्ली

किसानों की समृद्धि के लिए कृषि उपकरणों तथा उर्वरकों को जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए

बाल श्रम निषेध दिवस पर चिंतन हो

हर वर्ष 12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज को बाल श्रम की गंभीर समस्या के प्रति जागरूक करना है। दुर्भाग्यवश आज भी भारत सहित विश्व के कई देशों में बाल श्रम एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। गरीब और पिछड़े परिवारों के बच्चे मजबूरी में छोटी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं। सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे 'बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम' फिर भी इनका पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कई बार ये बच्चे घरेलू कामों, कारखानों, होटल-ढाबों, निर्माण स्थलों या खेतों में काम करते हुए मिलते हैं। बाल श्रम के साथ-साथ बच्चों के गुम होने की घटनाएं भी चिंता का विषय है। बच्चों का बचपन उन्हें लौटाना ही सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस की सार्थकता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

हादसों की एक वजह रील बनाना भी

पिछले दिनों आगरा में रील बनाते हुए छह बहिनें यमुना नदी में बह गईं। संभवतः रील बनाते हुए एक साथ हुई मौतों के लिहाज से ये देश का सबसे बड़ा हादसा है। वैसे रोज ही रील बनाते हुए या हेडफोन पर गाने सुनते हुए हादसों से हुई मौत की खबरें आती है। रोजाना अनेक सड़क दुर्घटनाएं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने के कारण होती है। मोबाइल आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा है इसलिए इन हादसों को रोकने में एक हद के बाद कानून भी बहुत मददगार नहीं हो सकता। लोगों अपनी समझ और विवेक से ही इन हादसों से बच कर मोबाइल को दुश्मन की जगह दोस्त बना सकते हैं।

बृजेश माथुर, गाजियाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के 'कैरियर स्ट्राइक ग्रुप' ने उत्तरी अरब सागर में 'पैसेज' अभ्यास (पासेक्स) में हिस्सा लिया। यह अभ्यास 9 और 10 जून को आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट 'आईएनएस तबर', पनडुब्बी और पी8आई विमान ने भाग लिया।

हिन्दुस्तान
1936

लू हवाले शहर

आजकल गर्मी से तपते उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों के लिए यह एक बुरा अनुमान है कि इनमें से अनेक शहरों में लू चलने के दिन दोगुने हो जाएंगे। मात्र पांच वर्ष के समय में न केवल लू के दिन बढ़ जाएंगे, बल्कि बारिश भी अनियमित हो जाएगी। जो लोग अभी तक बढ़ती गर्मी या बिगड़ते जलवायु के प्रति सचेत नहीं हैं, उन्हें यह जरूर जान लेना चाहिए कि साल 2030 तक दिल्ली, पटना, मुंबई, चेन्नई, सूरत, ठाणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में लू के दिन दोगुने हो जाएंगे। आईपीई ग्लोबल और एसरी इंडिया द्वारा किया गया यह अध्ययन हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भी हम गर्मी या गर्मी के दिनों पर अंकुश लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। शहरों में पेड़ों की बेरहम कटाई और जलस्रोतों-जलाशयों की घोर उपेक्षा का क्रम जारी है। हमारे शहर अपनी पवित्र नदियों को भी बचाने में नाकाम हो रहे हैं। गौर करने की बात है कि गर्मी की समस्या एकतरफा नहीं है। इसका एक परिणाम यह होगा कि देश के दस में से आठ जिलों में जरूरत से ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। मतलब, न केवल गर्मी का कहर बढ़ेगा, अत्यधिक बारिश भी वार करेगी।

यह याद रखने की जरूरत है कि साल 1993 से 2024 के बीच भारत में लू के दिन 15 गुना बढ़े हैं, अतः आगामी पांच वर्ष में अगर लू के दिन दोगुने हो जाएं, तो आश्चर्य नहीं। विगत तीन दशक में पर्यावरण के बिगड़ने की रफ्तार तेज रही है और इससे केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। हमें सावधान हो जाना चाहिए कि गर्मी के चलते ग्रीनलैंड की बर्फ औसत से 17 गुना अधिक तेजी से पिघली है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जलवायु में परिवर्तन कोई भविष्य की समस्या नहीं है, यह आज की समस्या है और इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से जलवायु में होने वाले बदलाव व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। खबरें बार-बार बता रही हैं कि ग्लेशियर और बर्फ की चादरें सिकुड़ रही हैं। ठंडे देशों में नदी और झील की बर्फ समय से पहले ही पिघल जा रही है। प्राकृतिक स्थिरता खो गई है। अब पौधों और जानवरों की भौगोलिक सीमाएं भी बदलने लगी हैं। पौधों और पेड़ों को भी जल्दी मची है। फूल-फल भी जल्दी खिलने-पकने लगे हैं। विश्व स्तर पर यह ज्यादा चिंता की बात है कि समुद्री बर्फ में कमी आ रही है, जिससे समुद्री जल स्तर में तेज वृद्धि हो रही है। इससे अनेक द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ा है। इसी अनुपात में लू या गर्म दिनों में भी वृद्धि हो रही है।

साल 1993 से 2024 के बीच भारत में लू के दिन 15 गुना बढ़े हैं, अतः आगामी पांच वर्ष में अगर लू के दिन दोगुने हो जाएं, तो कतई आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

मतलब, विश्व स्तर पर जलवायु बचाव के बड़े उपाय आजमाने की जरूरत है। देश और दुनिया के जिम्मेदार लोग और संस्थाएं भले ही मुंह चुराएं, मगर वैज्ञानिक प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट हैं। जलवायु परिवर्तन पूरे जीव-जगत के कल्याण और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। हमें कतई इंतजार नहीं करना चाहिए कि आपदाएं हमारे द्वार पर आ खड़ी हों, तभी हम जागेंगे। बेशक, भारत सीएफएल बल्ब और हरित वाहनों के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, पर पर्यावरण के बचाव के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हरित ऊर्जा पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए आंखें मूंदे रहने से आपदाएं नहीं टला करतीं। और जब हमें पता है कि हमारे शहर आने वाले वर्षों में ज्यादा आपदाएं झेलने वाले हैं, तो हमें ज्यादा सचेत होकर बचाव के उपाय करने चाहिए। निस्संदेह, शहरों को उनके अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन से बचाना होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 12 जून, 1950

पाकिस्तान से सौदे में अड़चनें

यह सर्वविदित है कि भारत व पाकिस्तान के व्यापार-सम्बन्ध ऐसे नहीं हैं, जैसे कि दो पड़ोसी देशों के बीच होने चाहिए। अब तक दोनों देश के बीच जो भी व्यापारिक समझौते हुए, वे पाकिस्तान द्वारा असफल कर दिये गये। पिछले कुछ दिनों से हमारी सरकार पाकिस्तान से 30 लाख टन गेहूं खरीदने की बातचीत कर रही है। परन्तु, हवा के रुख से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अड़चनों के बीच में आ जाने से यह बातचीत सफल नहीं हो सकेगी। पहली अड़चन तो यह है कि पाकिस्तान सरकार 10 रु. मन पर भी गेहूं देने के लिए तैयार नहीं है; और दूसरी यह कि वह रुपये की अपनी निश्चित विनिमय दर के हिसाब से मूल्य मांगती है। भला, भारत को ऐसी क्या आवश्यकता है कि जब उसे 10 या 10.5 रु. मन गेहूं अन्य देशों से मिलता है तो वह डेढ़ गुना दाम देकर पाकिस्तान से गेहूं खरीदे।

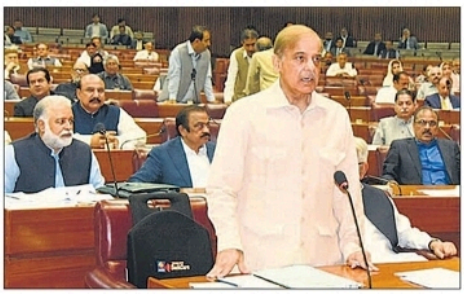

जो हो, पाकिस्तान की यह दर उसे स्वयं हानि पहुंचा रही है। पाकिस्तान कृषि उत्पादन में निःसन्देह भारत से आगे है। किन्तु, उसके इस उत्पादन के लिए भारत के अतिरिक्त पर्याप्त मण्डियां नहीं मिलतीं। इसी कारणवश पाकिस्तान में अन्न के भाव निरन्तर गिर रहे हैं। कुछ मास पूर्व पाकिस्तान की मण्डियों में गेहू का भाव 10 रु. मन था। परन्तु, आज वहां गेहूं का भाव गिरकर 6.5 रु. मन तक पहुंच गया है। बहावलपुर में तो भाव पौने 5 रु. मन तक गिर गया बतलाते हैं और यदि पाकिस्तान के निर्यात का यथेष्ट प्रबन्ध नहीं हुआ, तो ये भाव और गिर जायंगे। यहां बैठे हुए हम चाहे यह भले ही सोचें कि खाद्य-पदार्थों के दाम गिरने से पाकिस्तान के लोग समृद्ध व सुखी हो गये हैं, किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। पाकिस्तान में लोगों की आमदनी भारत की अपेक्षा बहुत कम है। दूसरे, पाकिस्तान कोयला, लोहा, चीनी व दैनिक इस्तेमाल में आने वाली अन्य वस्तुओं के लिए दूसरों का मुखापेक्षी है। यदि पाकिस्तान ये वस्तुएं डालर व पौण्ड वाले देशों से मंगाए, तो उसका निर्यात व्यापार जो पहले ही घाटे का है, और भी कम हो जायेगा। अतः भारत ही एक ऐसा देश है, जहां से वह इन वस्तुओं को खरीदकर अपनी डालर व पौण्ड निधि सुरक्षित रख सकता है। परन्तु, वह तो भारत की आर्थिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है।

पाकिस्तान में रक्षा बजट बढ़ने के मायने

पाकिस्तानी फौज अपने अवाम में यह भ्रम बनाए रखने में सफल रही है कि भारत उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी आड़ में वह बजट का बड़ा हिस्सा अपने नाम करा लेती है।

यहां स्कैन करें

जी जी द्विवेदी | सेवानिवृत्त मेजर जनरल

हिंदी में एक मुहावरा है, सिर ओखली में देना। पाकिस्तान की अभी वही दशा है। हाल ही में उसे ऑपरेशन सिंदूर में करारी मात मिली है। चीन, सऊदी अरब जैसे देशों के आगे हाथ फैलाने के अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से वह कर्ज मांग रहा है, ताकि पुराने कर्जे का ब्याज चुका सके। देश के कई हिस्सों में लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रखी है। मगर अपने लोगों को सुकून की जिंदगी देने के बजाय वह हथियारों पर अपने पैसे खर्च करने में जुटा है। मंगलवार को पेश पाकिस्तान के बजट का काफी हद तक यही निहितार्थ है।

इस बार के बजट में पाकिस्तान ने रक्षा मद में 20 फीसदी ज्यादा खर्च करने का एलान किया है। यानी, इस वित्तीय वर्ष में फौज पर उसका जो खर्च 7.45 अरब डॉलर था, उसे बढ़ाकर अब नौ अरब डॉलर कर दिया गया है। यह नई प्रवृत्ति नहीं है। चूंकि पाकिस्तान की फौज ही वहां परोक्ष रूप से शासन संचालित करती है, इसलिए उसे अपना बजट बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं आती। पहले भी वह ऐसे ही करती रही है, फिर चाहे वह आर्थिक रूप से विपन्न रहे।

असल में, पाकिस्तानी फौज अपने देश के अवाम में यह भ्रम बनाए रखने में सफल रही है कि भारत उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उसकी विश्वसनीयता इसी तर्क पर टिकी है कि भारत को वह सबसे बड़े खतरे के रूप में पेश करे। मंगलवार को बजट पेश करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की गई और कहा गया कि भारत द्वारा किए गए 'हमले' में गंभीर नुकसान होने के कारण बजट बढ़ाया जा रहा है। पिछले बजट में उसने बलूचिस्तान का राग अलापते हुए कहा था कि भारत बलूचों की मदद करके पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को खत्म करना चाहता है। चूंकि बलूचिस्तान में हुकूमत से खफा लोग लगातार विद्रोह करते रहते हैं, इसलिए शेष पाकिस्तान की जनता फौज की मनगढ़ंत बातों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेती है।

हालांकि, पाकिस्तान की इस दुर्दशा में उसके राजनेताओं का बड़ा हाथ है। उनके भ्रष्ट आचरण की खबरें आम पाकिस्तानी को फौज पर अधिक विश्वास करने को प्रेरित करती हैं। वैसे भी, वहां तो सरकार महज एक मुखौटा है, असली कमान फौज के पास ही है, जो उसकी प्रमुख नीतियां तय करती है, फिर चाहे वह विदेश नीति हो या सुरक्षा नीति।

पाकिस्तानी बजट का यह गणित चीन के काफी मुफीद है। दरअसल, पाकिस्तान अब अपने ज्यादातर हथियार चीन से खरीदता है। इसके कारण उसके बजट का बड़ा हिस्सा बीजिंग के खाते में जाता है। अगर पैसों के लेन-देन में कुछ कमी होती भी है, तो चीन उसे उधार या कर्ज देने में हिचकता नहीं। अपनी इसी नीति के बूते उसने कई देशों में जमीनें हथियाई हैं और उनकी संप्रभुता को खत्म किया है। श्रीलंका का हंबनटोटा हो या फिर पाकिस्तानी ग्वादर बंदरगाह, चीन की विस्तारवादी नीति के ये शिकार रहे हैं। पाकिस्तान के फौजी हुक्मरां पहले रक्षा और विदेश नीति ही तय करते थे, लेकिन अब वे उसकी आर्थिक नीतियां भी तय करने लगे हैं। वे चीनपरस्त नीतियों में ही अपना हित देख रहे हैं। यही कारण है कि चीन का काफी निवेश पाकिस्तान में लगा है। यहां तक कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सीईओ भी एक फौजी ही है।

चीन और पाकिस्तान का यह गठबंधन राजनीतिक कम और सैन्य ज्यादा है। मैं जब चीन में 'डिफेंस अटैची' की अपनी सेवा दे रहा था, तब मैंने खुद महसूस किया था कि चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी किस तरह से एक-दूसरे से गलबहियां करते रहते हैं। दोनों देश की सेनाएं समान सोच पर आगे बढ़ती हैं। अब चूंकि इस्लामाबाद को बीजिंग से उन्नत हथियार भी मिलने लगे हैं, जैसे स्टील्थ फाइटर जे-35 विमान भी अब पाकिस्तानी बेड़े का हिस्सा बन रहा है, तो यह दोस्ती अभी आगे और बढ़ेगी ही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से चीन के हथियारों से उसने भारत का मुकाबला किया। ऐसे में, पाकिस्तान यदि अपने रक्षा बजट को बढ़ाता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा परोक्ष रूप से चीन ही पहुंचेगा। यानी, दोनों देशों के लिए बजट राशि में बड़ी बढ़ोतरी मुफीद स्थिति ही मानी जाएगी।

मगर यह तस्वीर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब यह साफ हो गया है कि चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ है। पहले हम जरूर कहते थे कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस तरह अब हम दो फ्रंट पर नहीं लड़ रहे, बल्कि एक ही फ्रंट पर लड़ रहे हैं और हमारा मुकाबला अब चीन-पाकिस्तान गठबंधन से है। पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को किस तरह आगे बढ़ा रहा है, इसकी तस्दीक इससे भी होती है कि चीन, रूस, तुर्किये, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ गठबंधन में उसकी एक बड़ी भूमिका नजर आती है। चूंकि भारत को घेरने के लिए बीजिंग नित नई चालें चलता है, इसलिए पाकिस्तान को उसने अपने अधीनस्थ कर लिया है और नई दिल्ली के खिलाफ अपनी नीतियों को अंजाम देने में उसका साथ देता दिख रहा है।

अब हमें तय करना होगा कि हम किधर जाएंगे? पहले हम अमेरिका और रूस, दोनों के साथ दोस्ती के पक्षधर थे। मगर पिछले दिनों हमने देखा है कि रूस और चीन काफी करीब आए हैं। इस दोस्ती में भी दुखद पहलू यह है कि चीन नेतृत्व की भूमिका में है और रूस सहयोगी की। यही कारण है कि भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहिए। अगर हम यह मानकर चल रहे हैं कि दुनिया के जिन तीन देशों में स्टील्थ फाइटर हैं, उनमें रूस भी है और वह हमारी मदद करेगा, तो यह दिवास्वप्न साबित हो सकता है। रूस के अलावा अमेरिका और चीन के पास ही ऐसे लड़ाकू विमान हैं। ऐसे में, यदि रूस हमारी मांगों पर गौर करेगा भी, तो पहले चीन से अनुमति लेगा और वहां से हरी झंडी मिलने से रही। हमें अपनी सामरिक और विदेश नीति में बदलाव लाना चाहिए। यह वक्त की एक बड़ी मांग है।

रही बात पाकिस्तान की, तो उस पर हम हमेशा बीस ही साबित हुए हैं। मगर यदि चीन का उसे खुलकर साथ मिलता है, तो हमें भी अपने रक्षा बजट में इजाफा करना पड़ सकता है। वैसे भी, जब पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश हो, तो अपनी रक्षा पंक्ति पर खर्च करना हमारी जरूरत ही है। हमारा सत्ता प्रतिष्ठान इस नई परिस्थिति के अनुरूप अवश्य कदम उठाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भीड़ प्रबंधन के लिए हमें एक राष्ट्रीय नजरिया चाहिए

यहां स्कैन करें

ओ पी सिंह | पुलिस महानिदेशक, हरियाणा

भारत अपने जलसों-जनसमूहों से फलता-फूलता रहा है। चाहे क्रिकेट की जीत के जश्न हों, राजनीतिक रैलियां हों, धार्मिक उत्सव हों या फिर सेलीब्रिटी के कार्यक्रम, हजारों, बल्कि कई बार तो लाखों का हुजूम सड़कों पर, मैदानों में उमड़ आता है। यह भीड़ हमारे देश की जीवंतता तो प्रदर्शित करती है, मगर वह सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौती भी पेश कर देती है।

हाल के दिनों में हुई त्रासदियों ने भीड़ के कुप्रबंधन को उजागर किया है। इस समस्या का समाधान केवल सख्त पुलिस निगरानी या हादसे के बाद की जांच से नहीं किया जा सकता है। इसका हल व्यवस्थित योजना में है और इस मामले में हमारे देश का प्रशासन अक्सर कमजोर साबित होता है। भारत में भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले वार्षिक तीर्थयात्राओं या चुनावी रैलियों की भीड़ का आकलन करना आसान था, मगर अब तो सोशल मीडिया से प्रेरित होकर मिनटों में अचानक भारी भीड़ जमा हो जाती है। अचानक जमा होने वाली यह प्रवृत्ति ज्यादातर कस्बाई इलाकों में देखी जाती है, जहां भीड़ को संभालने की कोई मशीनरी नहीं होती। इनको संभालने के लिए बैरिकेड लगाने, लाठीचार्ज आदि की पारंपरिक व्यवस्थाएं लगातार बेमानी होती जा रही हैं। हमारी पुलिस कुशल और साहसी है, मगर इस तरह की समस्या से निपटने के लिए जरूरी साजो-सामान से लैस नहीं है।

हमारी पुलिस कुशल और साहसी है, मगर अचानक उमड़ आई भीड़ की समस्या से निपटने के लिए जरूरी साजो-सामान से लैस नहीं है।

भारत को भीड़ प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे की तत्काल आवश्यकता है, जो भीड़ के आकार, आयोजन के प्रकार और स्थानीय बुनियादी ढांचे के अनुरूप लचीली व बहुस्तरीय प्रणाली हो। भीड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल जिला पुलिस पर छोड़ना उचित नहीं है। इसे शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों में शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर संयुक्त संचालन केंद्र (जेओसी) गठित होने से भी समन्वय के तरीके बदल सकते हैं। पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य टीमें, परिवहन विभाग और नगर पालिकाएं सामूहिक रूप से एक स्पष्ट कमांड के तहत काम करती हुई दिखें। जेओसी फैसलों और संसाधनों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन सक्रियता से कदम उठाए जा सकें।

कई शहरों में पहले से ही सीसीटीवी नेटवर्क और ड्रोन निगरानी प्रणाली मौजूद हैं। इन्हें एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) संचालित भीड़ प्रबंधन व जन-सघनता की जांच करने वाले ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से जोड़कर उचित समय पर अलर्ट किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि देश की अधिकांश पुलिस इकाइयों के पास ऐसे एकीकृत उपकरण नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के तहत इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसके लिए राज्यों को संसाधन मुहैया करा सकता है। इस काम में भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और शोध संस्थानों को भी लगाया जा सकता है। हमारे बहुत से शहरों में स्पष्ट चेतावनी संकेतकों, अनेक निकास द्वारों या सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रणाली का अभाव है। इसलिए स्मार्ट सिटी जैसे शहरी विकास कार्यक्रमों को अपनी नियमित विकास योजनाओं में भीड़ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुंभ या स्थानीय मेलों जैसे बार-बार होने वाले आयोजनों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। इसे अस्थायी तौर पर बनाए गए ढांचे से प्रबंधित किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं होगी, बस सटीक योजना बनाने की आवश्यकता है।

भारत जैसे विशाल देश में भीड़ को पूरी तरह नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, पर इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत में इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिभाओं, उपकरणों और संस्थानों की कमी नहीं है, बस नीति और क्रियान्वयन, केंद्र, राज्य और स्थानीय एजेंसियों में तालमेल की जरूरत है। भारत जैसे देश में, जहां लोग इकट्ठा होते ही रहेंगे, सार्वजनिक सुरक्षा अपनी प्रणालियों को व्यवस्थित करने में निहित है। समय आ गया है कि हम बेहतर योजना बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि भारत के ये जीवंत धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन जोखिम का नहीं, बल्कि गर्व का स्रोत बनें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मिलकर शक्ति बढ़ाएं

गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से राम जी पहली बार घर से निकले थे ऋषि विश्वामित्र जी के साथ, ऋषि व मानवता की सेवा के लिए। राम जी के मुख से बोल भी तभी पहली बार निकले थे। तुलसीदास जी ने पहली बार राम जी को बोलते हुए विश्वामित्र जी के साथ ही दिखाया है।

वन-आश्रम में जब यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, तब सबसे पहले राम जी ने जो कहा, उसे तुलसीदास जी ने लिखा। वह सावधान थे कि जब राम-वचन की शुरुआत करूंगा, तो जिसके लिए ईश्वर ने अवतार लिया है, उसके लिए करूंगा। सबसे पहले राम जी ने कहा – *निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई।* अर्थात, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। रामजी ने विश्वामित्र जी से कहा, जो राक्षस आएंगे, उन्हें मैं कालकलवित कर दूंगा।

यज्ञ धर्म का सबसे बड़ा कृत्य है। देवता जितना देते हैं, उसके बदले में हम भी उन्हें दें। उनका अभिनंदन करें, तब हमारी मानवता, हमारा व्यक्तित्व देवत्व को प्राप्त करेगा। जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई यही होती है कि हम अपने बच्चे को कैसे ऊंचाई तक ले जाएं, तो विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी, दोनों का ऋषित्व मिलकर संसार के उपकार का मार्ग प्रशस्त करता है। लोग कहा करते हैं कि राम जी अद्भुत हैं, ऋषि के समान हैं। उन्होंने विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी को मिला दिया। कौशल्या और कैकयी की दूरी को कम कर दिया। उत्तर और दक्षिण को जोड़ दिया। वन, ग्राम और नगर को मिला दिया।

आज राम जी जैसा सोचने की जरूरत है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की तरह सोचने की जरूरत है। संतों और आचार्यों के जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना है, लेकिन अब तो सभी लोग धन एकत्र करने लगे हैं कि कैसे मठ बड़ा हो जाए, कैसे गाड़ियां बड़ी हो जाएं।

राम जी ने सबको जोड़ा और संपूर्ण मानवता के लिए अर्पित किया। असंख्य जीवों का उद्धार किया। कैसी अनुपमता जीवन में प्रकट हुई! इसी तरह के परिवर्तन आज के संत समाज में होने चाहिए। ऐसा हुआ, तो पूरे विश्व को लाभ होगा। धन, विद्या, शक्ति इत्यादि सबमें वृद्धि होगी। आज जो अभाव है, एक दूसरे को सहन नहीं करने से उपजा अभाव है। कहीं-कहीं लगता है कि केवल हम हम ही हों, दूसरा कोई न हो, यह गलत प्रवृत्ति है।

राम जी अद्भुत हैं, ऋषि के समान हैं। उन्होंने विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी को मिला दिया। कौशल्या और कैकयी की दूरी को कम कर दिया। उत्तर और दक्षिण को जोड़ दिया।

विश्वामित्र जी कहते थे कि हमारे एक हाथ में वेद है और दूसरे में धनुष। शास्त्र भी है और शक्ति भी है। जिसके जीवन में केवल शास्त्र ही हो, उसका जीवन अधूरा है और जिसके जीवन में केवल शक्ति हो, उसका जीवन अधूरा है। ध्यान देने की बात है कि हमने धन बल को बढ़ाया, तप बल को नहीं बढ़ाया, इसलिए देश लंबे समय के लिए गुलाम हो गया। भारतीय संस्कृति में केवल पढ़ना या शास्त्र तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है। हम केवल ज्ञानवान ही नहीं बनें, हमारे पास धन भी रहना चाहिए।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

पत्रकारिता में सिर्फ 'सबसे आगे' बने रहने की दौड़ न हो, बल्कि 'सबसे सही' बनने की जिम्मेदारी हो। आजकल 'वेरिफाइड' होने की जगह 'वायरल' होना पत्रकारिता का मानक बन गया है। इससे बचने की जरूरत है।

आयोग मतदाताओं की शंका दूर करे

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को फिर से घेरा है। उनके सवाल बिल्कुल स्पष्ट हैं- 2019 से 2024 के बीच राज्य में मतदाताओं की संख्या में 31 लाख की बढ़ोतरी हुई, लेकिन मई 2024 से नवंबर 2024 तक, यानी महज पांच महीने में ही 41 लाख नए मतदाता कैसे जुड़ गए? आखिर इतनी असामान्य वृद्धि हुई कैसे? और फिर, राज्य की वयस्क आबादी से अधिक मतदाता कैसे बन गए? राहुल गांधी इन्हीं नए मतदाताओं को फर्जी बता रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है, जो चंद महीने में होने वाला है। मजेदार बात यह है कि उन्होंने सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं, लेकिन जवाब सत्तारूढ़ दल के नेतागण दे रहे हैं। खबर यह भी है कि चुनाव आयोग ने जो कथित तौर पर अपना बयान मीडिया में जारी किया, उसमें उस अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं, जिन्होंने बयान लिखा है। चूंकि लोकतंत्र की जीवंतता के लिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अनिवार्य है, इसलिए राहुल गांधी के सवालों का जवाब आयोग को देना ही चाहिए। अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है, तो परोक्ष रूप से भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठेंगे। व्यापक देशहित में चुनाव आयोग को आगे आकर स्थिति साफ करनी चाहिए।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों पर उचित ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सिलसिलेवार और विस्तार से बताया है कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित किया गया। लगता यही है कि एक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर सुनियोजित तरीके से धांधली की गई। दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते दिख रहा है। वह ढंग से जवाब तक नहीं दे रहा। सिर्फ रटी-रटाई बातें कही जा रही हैं कि आरोपों में दम नहीं है या हम इसको खारिज करते हैं। जबकि, सवाल जब तथ्यों के साथ पूछे गए हैं, तो जवाब भी उसी तरह तथ्यों के साथ आने चाहिए। चुनाव आयोग की नीयत पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीने में ऐसे कई बदलाव हुए हैं, जिनसे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता कठघरे में आई है। आखिर चुनाव आयोग मतदान का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी कर रहा? मतदाता सूची से संबंधित डाटा को क्यों नहीं जारी कर रहा? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचन आयोग पर यूं सवाल उठना बहुत गंभीर बात है।

महिमा सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

चुनाव आयोग

आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होता

लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरने से बाज नहीं आते। एक बार फिर उन्होंने चुनाव आयोग को घेरने की विफल कोशिश की है और महाराष्ट्र चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और अदालत तक मामला पहुंचा था, लेकिन न सिर्फ चुनाव आयोग, बल्कि शीर्ष अदालत ने भी अपनी जांच में उनकी शिकायतों को बेबुनियाद माना था। ऐसे में, यही कहना उचित है कि कांग्रेस नेता बेवजह के आरोप लगाते रहते हैं और हर बार जगहंसाई के पात्र बनते हैं। तय है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी उचित ही इसे महाराष्ट्र चुनाव हारने की हताशा बता रही है। लगता यही है कि कांग्रेस चूंकि लंबे समय से सत्ता से दूर है, इसलिए उसके नेता अब अधीर हो रहे हैं और चुनाव-दर-चुनाव मिल रही हार को पचा नहीं पा रहे। यही कारण है कि वे जैसे-तैसे सत्ता पाने की जुगत में हैं। राहुल गांधी के सवाल इन्हीं कोशिशों का नतीजा हैं। मगर ऐसा करते हुए वह शायद भूल रहे हैं कि अपने दावों से वह खुद अपना उपहास उड़ाते हैं।

मनमोहन राजावत, टिप्पणीकार

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग की है कि चुनाव आयोग साक्ष्यों के साथ यह साबित करे कि उसके द्वारा कराए गए चुनाव में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है या हो रही है। चुनाव आयोग का उत्तर है कि राहुल गांधी प्रामाणिक साक्ष्य के साथ शिकायत करें, तो उनको प्रमाण सहित जवाब दिया जाएगा कि उनके द्वारा की गई शिकायत सर्वथा आधारहीन और तथ्यों से परे है। चूंकि राहुल गांधी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, इसलिए चुनाव आयोग उनके आरोपों को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सिरे से खारिज कर रहा है। वैसे भी, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें ईवीएम के बनने से लेकर रखरखाव, जांच, उसे सीलबंद करने व सील खोलने तथा ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती तक, धांधली या छेड़छाड़ की आशंका शून्य होती है। यही कारण है कि राहुल गांधी के पूर्व के आरोप भी हकीकत की धरातल पर टिक नहीं सके। यह बात राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। वह तो सिर्फ सियासी मकसद के लिए चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास करते रहते हैं। चूंकि, सब कुछ जानते हुए भी आधारहीन और तथ्यहीन दावा करना राहुल गांधी की फितरत है, ऐसे में, उनके द्वारा पेश किए गए तथ्य को स्वीकार कर लिया जाएगा, यह संभव नहीं दिखता। बेहतर होगा कि वह मतदाताओं का भरोसा जीतें।

दिनेश सिंह, टिप्पणीकार

ग़लत राह पर पाक

पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% का इजाफा किया है। इससे उसकी प्राथमिकता साफ हो जाती है कि उसके लिए अपनी जनता का कल्याण और विकास नहीं, भारत के खिलाफ आक्रामकता ज्यादा जरूरी है। यह बात और है कि बजट का 14.5% सिर्फ डिफेंस पर खर्च करके वह अपनी मुश्किलें ही बढ़ाएगा।

कर्ज पर गुजारा । लोन और आर्थिक मदद की वजह से ही पाकिस्तान अभी तक दिवालिया होने से बचा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से उस पर 269 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है, जबकि उसके मौजूदा बजट का आकार है केवल 63 बिलियन डॉलर। जाहिर है, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने की आदत ने पाकिस्तान को ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया है, जहां अब उसे अपने बजट का करीब आधा हिस्सा कर्ज की किस्तों और ब्याज भरने के लिए देना पड़ेगा। अब जो रकम बचती है, उसमें से भी लगभग एक तिहाई यानी 9.17 बिलियन डॉलर उसने डिफेंस के लिए रख लिया है।

AI Image

डिफेंस बजट 20% बढ़ाया

भारत से तुलना । इस्लामाबाद में नई दिल्ली के साथ होड़ करने की बेचैनी और उतावलापन है। उसे भले समझ न आए, लेकिन सच यही है कि इतने भारी खर्च के बावजूद भारत के 77 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट के सामने पाकिस्तान का रक्षा बजट बहुत मामूली है। हां, यह जरूर है कि यह होड़ उसे कर्ज, खासकर चीन के कर्ज के जाल में और फंसा रही है। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी देनदारी चीन की है, लगभग 15 बिलियन डॉलर।

चीन का फायदा । पाकिस्तान अपने लगभग 80% सैन्य साजो-सामान और हथियार चीन से खरीदता है। चीन J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी पाकिस्तान को देने जा रहा है। यानी उसके सैन्य बजट का एक बड़ा भाग चीन की जेब में जाएगा। यही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने बजट में कर्ज अदायगी के लिए जो रकम रखी है, उससे भी सबसे बड़ा हिस्सा चीन को मिलेगा। विडंबना है कि भारत के साथ टकराव के दौरान पाकिस्तान को चीनी डिफेंस सिस्टम की वजह से ही नुकसान और शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी।

आर्थिक मुश्किलें । पाकिस्तान को हथियार से ज्यादा रोजगार, निवेश और अन्न की जरूरत है। उसकी इकॉनमी एक अरसे से जड़ बनी हुई है। 2025 में GDP ग्रोथ का अनुमान 2.7% है। आर्थिक मोर्चे पर उसकी सबसे बड़ी खुशी यह है कि IMF ने हाल में एक नए बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान का बजट भारत की चिंताओं की पुष्टि करने के साथ IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को भी आईना दिखाता है। ये संस्थाएं बार-बार भरोसा टूटने के बावजूद पाकिस्तान के किसी नए वादे के झांसे में आकर मदद देती रहती हैं। क्या अब वे सबक लेंगी?

साड्डी दिल्ली

बड़े लोगों के बंगले

विवेक शुक्ला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शामनाथ मार्ग के दो बंगले -1/8 और 2/8 - अलॉट हुए हैं। यानी उन्हें अरविंद केजरीवाल के 6, फ्लैग स्टाफ रोड के करीब ही बंगला मिला है। शामनाथ मार्ग और फ्लैग स्टाफ रोड करीब ही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इनमें से एक बंगले में रहेंगी और दूसरे में होगा उनका दफ्तर।

जानना दिलचस्प होगा कि 3, फ्लैग स्टाफ रोड में बहू बनकर बॉलिवुड स्टार रेखा 1990 में आई थीं। 4, फ्लैग स्टाफ रोड में कभी सलमान रुश्दी का परिवार रहता था। अगर बात गुजरे दौर की करें तो दिल्ली के दो मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश और फिर मदन लाल खुराना 33, शामनाथ मार्ग के बंगले में रहे। उसे कथित तौर पर 'मनहूस' माना जाता है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश को 1955 में उनके पद से हटा दिया गया था, जबकि खुराना को 1996 में जैन हवाला मामले में नाम आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इन घटनाओं का कितना असर था पता नहीं, लेकिन खुराना के उत्तराधिकारी साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 9, शामनाथ मार्ग के बंगले में ही रहे, जो उन्हें खुराना के मंत्रिमंडल में मिला था।

कहा जाता है कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने 33, शामनाथ मार्ग में कभी एक रात भी नहीं बिताई। वह हमेशा अपने दिल्ली देहात वाले घर में रहे। उनके बाद गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बने। वह हमेशा अपने रूप नगर वाले घर में रहे। आगे चलकर वह राजस्थान के राज्यपाल भी बने। उनके पुत्र एस. निहाल सिंह इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे। बहरहाल, 1999 में कांग्रेस के सत्ता में आने पर शीला दीक्षित ने एबी-17, मथुरा रोड बंगले में रहना पसंद किया। वह 2005 तक वहां रहीं। यह वही बंगला है, जो बाद में AAP सरकार में मंत्री बने मनीष सिसोदिया और फिर आतिशी को आवंटित हुआ। आतिशी मुख्यमंत्री बनने पर भी यहीं रहीं। अपने दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस हाईकमान ने शीला दीक्षित से बड़े आवास में रहने को कहा, तब वह 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग चली गईं। यह करीब 3.5 एकड़ का टाइप-8 बंगला है। यह बंगला प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 2014 में डॉ. मनमोहन सिंह को आवंटित हुआ था। इसमें ही उनका पिछले साल 26 दिसंबर को निधन हुआ।

एकदा

पढ़ाई से प्रेम

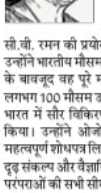

20वीं सदी के दूसरे दशक की बात है। तब परंपरागत सोच यह थी कि बेटियों को शादी के लिए और बेटों को करियर बनाने के लिए तैयार किया जाए। 1918 में त्रावणकोर के एक समृद्ध परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था- अन्ना मोदायिल मणि। अन्ना मणि को बचपन से ही किताबों से गहरा लगाव था। आठ साल की उम्र में उन्होंने स्थानीय लाइब्रेरी की लगभग सभी मलयालम किताबें पढ़ डाली थीं। उनमें पढ़ाई के प्रति जो ललक थी, उसका उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन कोई भी विरोध उन्हें पढ़ाई से दूर नहीं कर सका। कॉलेज के बाद उन्हें भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में नोबेल विजेता सी.वी. रमन की प्रयोगशाला में शोध का अवसर मिला। 1948 में उन्होंने भारतीय मौसम विभाग में काम शुरू किया। सीमित संसाधनों के बावजूद वह पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटी रहीं। उन्होंने लगभग 100 मौसम उपकरणों की डिजाइन को मान्यता दिलाई और भारत में सौर विकिरण मापने वाले स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया। उन्होंने ओजोन, विकिरण और मौसम विज्ञान पर कई महत्वपूर्ण शोधपत्र लिखे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक सोच के जरिए कोई भी व्यक्ति समाज और परंपराओं की सभी सीमाओं को तोड़ सकता है।

Subrata Dhar

संकलन : चंदन कुमार झा

दुर्लभ खनिज से बने शक्तिशाली चुंबकों के निर्यात पर रोक से भारत के रक्षा और वाहन उद्योग पर संकट

रेयर अर्थ के बहाने चीन ने चली नई चाल

रंजीत कुमार

अपने दुश्मन या प्रतिस्पर्धी देशों की सैन्य व आर्थिक ताकत कमजोर करने का चीन ने एक नायाब तरीका निकाला है। उसने नई निर्यात नीति जारी की है, जिसके तहत दुर्लभ खनिज से बने शक्तिशाली चुंबक जैसे संवेदनशील उच्च तकनीकी उत्पादों का आयात हथियारों के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले से न केवल भारत का आधुनिक नागरिक उद्योग संकट में आ गया है बल्कि रक्षा उद्योग के लिए भी समस्या पैदा होगी।

दोहरे इस्तेमाल पर ऐतराज । आधुनिक तकनीक से बने वाहनों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में जिन शक्तिशाली चुंबकों का इस्तेमाल होता है, उनके दुनिया भर में 90% से अधिक उत्पादन पर चीन का कब्जा है। इस ताकत की बदौलत उसने प्रतिद्वंद्वी देशों की व्यावसायिक और सामरिक ताकत को कमजोर करने की चाल चली है। उसने कहा है कि नागरिक और सैन्य इस्तेमाल वाले उत्पादों का आयात जो देश चीन से करेंगे, उन्हें यह गारंटी देनी होगी कि चीनी उत्पाद का इस्तेमाल केवल नागरिक उद्योगों के लिए ही किया जाएगा।

सप्लाई का संकट । चीन के इस कदम से भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों के वाहन व अन्य आधुनिक उद्योगों के सामने तात्कालिक तौर पर चुंबकों की कमी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि एक महीने के भीतर चुंबकों की सप्लाई नहीं हुई तो उनके कारखानों में वाहनों का उत्पादन रुक सकता है।

क्या है चीनी पैंतरा
- रेयर अर्थ से बने चुंबकों के निर्यात पर चीन ने लगाई नई शर्त
- भारत समेत अमेरिका और यूरोपीय देशों की चीन पर है निर्भरता
- सप्लाई में अचानक आई कमी बन गई है गंभीर चुनौती

व्यापारिक टकराव का बहाना । चीन कह रहा है कि उसकी यह नीति अमेरिका द्वारा उसे होने वाले उच्च तकनीक निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में लागू की गई है। लेकिन जानकारों के मुताबिक चीन ने अमेरिका से चल रहे व्यापारिक टकराव को बहाना बनाया है। मकसद यह है कि चीन से होड़ करने वाले देशों को उसकी दया पर निर्भर बनाया जा सके।

अमेरिका की नकल । अमेरिका ने पिछले कई दशकों से एक टेक्नॉलजी डिनायल रेजीम यानी दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक के निर्यात पर रोक लगाने वाली व्यवस्था चलाई है ताकि वह भारत जैसे तेजी से उभर रहे देशों की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा सके। चीन ने इसी तकनीक प्रतिबंध नीति का अनुसरण किया है। वास्तव में अमेरिका भी यह सुनिश्चित करता है कि उसकी उच्च तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ साथी देश ही कर पाएं।

चीन की संभावित शर्त । विदेश मंत्रालय ने राजनयिक स्तर पर चीन से चर्चा की है, लेकिन उसने कोई वादा नहीं किया है। ऐसे में भारतीय कारोबारियों ने चीन सरकार से प्रत्यक्ष बात करने के लिए अपना एक दल पेइचिंग भेजने का फैसला किया है। लेकिन चीन ऐसे ही नहीं मानेगा। वह अपनी एक इंस्पेक्शन टीम भेजने की शर्त लगा सकता है। टीम यह देखेगी कि चीन से आयातित दोहरे उपयोग वाले चुंबकों का इस्तेमाल कहां और कितना हुआ। यदि भारतीय उद्योग यह शर्त मान लेता है तो कई संवेदनशील व्यावसायिक व सामरिक जानकारी चीन के हाथ लग सकती है।

चार गुना बढ़ा आयात । पिछले पांच वर्षों में भारत में चीनी शक्तिशाली चुंबकों का आयात 12400 टन से करीब चार गुना बढ़कर 53,700 टन हो गया है जो कि भारत की कुल जरूरतों का 93% है। ऐसे में भारतीय उद्योग के समक्ष यह संकट पैदा हो गया है कि इतनी भारी मात्रा में चुंबकों की जरूरत तुरंत कैसे पूरी हो।

चीन पर बढ़ी निर्भरता । दुर्लभ खनिजों के खनन और उत्पादन के लिए भारत में सरकारी कंपनी रेयर अर्थ लि. है, लेकिन इसने इन खनिजों की राष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप खनन और उत्पादन पर समुचित निवेश इसलिए नहीं किया क्योंकि चीन से इनका आयात सस्ते में हो ही रहा था। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी चीन पर अपनी निर्भरता इसलिए बनाए रखी कि दुर्लभ खनिज का खनन और उत्पादन पर्यावरण को काफी प्रदूषित करता है।

भारत में विशाल भंडार । एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दुर्लभ खनिज का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार (69 लाख टन) है जबकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार (4 करोड़ 40 लाख टन) और ब्राजील के पास दूसरा बड़ा भंडार (2.10 करोड़ टन)। अपने भंडार से भारत ने मात्र 2900 टन दुर्लभ खनिज पैदा किया है जबकि चीन ने 2,55,000 टन।

भारत को अचानक पैदा हुई इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी। उसे न केवल दुर्लभ खनिज का वैकल्पिक स्रोत खोजना होगा बल्कि इसके उत्पादन की समुचित तकनीक भी हासिल करनी होगी। ऐसा न हुआ तो भारत को दुर्लभ खनिज पर आधारित अपने आधुनिक नागरिक व रक्षा कारखाने चलाने के लिए चीन का मोहताज होना होगा। सवाल है कि द्विपक्षीय रिश्तों के मौजूदा हाल के मद्देनजर क्या चीन भारत को यह ताकत हासिल करने में मदद करेगा?

(लेखक सामरिक मामलों के जानकार हैं)

US से भी छात्र भारत पढ़ने आएंगे बशर्ते...

मनीष सिसोदिया

न्यू यॉर्क के एक एयरपोर्ट से आया विडियो अभी भी मेरी आंखों में ठहरा है। बताया जा रहा है कि वह भारतीय युवक अमेरिका पढ़ने गया था। उसे चार सुरक्षाकर्मियों ने जमीन पर पटक दिया। हथकड़ियां पहनाईं, घुटनों से दबाया। विडियो में उसकी आवाज गूंजती है, 'मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मैं तो पढ़ने आया था..।' इस दृश्य के लिए हम अमेरिका को दोषी नहीं ठहरा सकते। कहा जा रहा है कि उस युवक के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। वैसे भी हर देश को अपनी वीजा नीति बनाने और उसे लागू करने का पूरा अधिकार है। सवाल है कि क्या यह समस्या केवल अमेरिका की कठोर वीजा नीति की है? या कहीं यह हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रतिबिंब है?

विकल्प सीमित । भारत हर साल दुनिया को सबसे ज्यादा छात्र देने वाले देशों में शामिल है। 2023 में ही 7.7 लाख से अधिक भारतीय छात्रों ने विदेश में पढ़ाई के लिए वीजा हासिल किया। अकेले अमेरिका में 2.7 लाख, कनाडा में 1.8 लाख और ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज्यादा छात्र पहुंचे। दूसरी ओर, भारत में करीब 1,100 विश्वविद्यालय और 43,000 से अधिक कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 4 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत कम ही संस्थान 'उत्कृष्ट' हैं।

मौजूदा शून्य । IITs, IIMs, IISc, AIIMS हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन संस्थानों में बेहद कम सीटें हैं। उदाहरण के तौर पर, हर साल लगभग 12 लाख छात्र IIT-JEE की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सीटें मुश्किल से 17,000 हैं। यानी हर एक सीट के लिए 1000 से ज्यादा छात्र प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। देश में उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या ही बेहद सीमित है। यही वह शून्य है, जिसे भरने के लिए छात्र विदेश की ओर रुख करते हैं।

भरोसे का संकट । यहां एक और गहरी बात छुपी है। भारत के कई अच्छे विश्वविद्यालय पढ़ाई के स्तर पर तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वे अपने छात्रों को भरोसा नहीं दे पाते कि वे उन्हें एक एक सक्षम प्रफेशनल या एक वैश्विक नागरिक बनाएंगे। यही वजह है कि कई बार छात्रों को लगता है, भले विदेशी कॉलेज टॉप रैंक में न हो, लेकिन वहां की पढ़ाई, exposure और सोच मुझे कुछ करने लायक बना देगी।

AI Image

कॉमन रूम

उलटा परिणाम । दूसरी ओर, भारत के बहुत से विश्वविद्यालय- विशेषकर निजी कॉलेज- केवल डिग्री बांटने की फैक्ट्री बन चुके हैं। वे न तो छात्रों में विश्वास भरते हैं, न कौशल, न सोच। हमारी सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी भी केवल एक अच्छी नौकरी के सपने तक ही सीमित रह जाती है।

देर नहीं हुई । विदेश में छात्रों के साथ हो रही घटनाएं एक चेतावनी भी हैं। भारत को अपनी उच्च शिक्षा नीति को सप्लाई-ड्रिवन से डिमांड-ड्रिवन, और डिग्री-ड्रिवन से माइंडसेट-ड्रिवन बनाना होगा। हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था केवल अच्छी नौकरी करने वाले युवाओं की फौज दे रही है। अपने दम पर कुछ कर गुजरने वाली मानसिकता नहीं दे पा रही।

नई शुरुआत । हमें एक नई शिक्षा नीति नहीं, एक नई शिक्षा दृष्टि की जरूरत है। वह दृष्टि जो देश के हर बच्चे को यह कहे कि तुम्हें अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा बेहतर इंसान बनने के लिए। देश को अब यह तय करना है कि हम हर साल लाखों छात्रों को सूटकेस के साथ एयरपोर्ट तक छोड़ने वाले राष्ट्र बने रहेंगे, या एक ऐसा देश बनेंगे जहां अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजें।

(लेखक दिल्ली के पूर्व शिक्षामंत्री हैं)

क्या विभाजन से अनजान थे बापू

टाइम मशीन

15 जून 1947, गर्मी की इसी दोपहर को कांग्रेस कार्यसमिति ने विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कार्यसमिति की बैठक में सदस्यों के अलावा दो और लोगों को बुलाया गया था, जयप्रकाश नारायण और डॉ. राम मनोहर लोहिया।

महात्मा गांधी का सख्त रुख । जब विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर लिया, तब महात्मा गांधी नोआखाली में थे। उन्हें जब जानकारी मिली, तो उन्होंने कठोर बयान दिया था - बंटवारा मेरी लाश पर होगा। गांधी जी के इस बयान से बंटवारे को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर चुके कांग्रेसी नेता हिल गए थे।

Subrata Dhar

नेहरू-पटेल से सवाल । लोहिया की किताब 'भारत विभाजन के गुनहगार' के अनुसार, कार्यसमिति की बैठक में गांधी जी ने बंटवारे के प्रस्ताव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें विभाजन की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बापू ने वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू से इस बारे में सवाल पूछा। इस पर नेहरू ने पहले कहा कि वह बापू को इस बारे में बराबर जानकारी देते रहे हैं। लेकिन, जब गांधी जी ने अपनी बात दोहराई, तो अपने कहे को थोड़ा बदलते हुए नेहरू बोले कि नोआखाली इतनी दूर है और वह उस योजना के बारे में विस्तार से ना बता सके होंगे। हालांकि उन्होंने गांधी जी को विभाजन के बारे में मोटे तौर पर लिखा था। नेहरू ने बाद में गांधी जी के नाम लिखे पत्रों को पब्लिश भी कराया था।

बात माननी पड़ी । बैठक में गांधी जी को जब आभास हो गया कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं ने विभाजन की योजना मान ली है, तो उन्होंने कार्यसमिति से अपील की - कांग्रेस दल अपने नेताओं के किए वादे को स्वीकार कर ले। वादा यानी विभाजन का प्रस्ताव। लोहिया ने लिखा है, 'बैठक में कांग्रेस दल के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ऊंघते हुए कुछ झुक कर बैठे थे। किसी मुद्दे पर बहस के दौरान महात्मा गांधी ने कांग्रेस के थके हुए अध्यक्ष की चर्चा की और मैंने गहरी झुंझलाहट से उनकी बांह को झिंझोड़ा। तब उन्होंने बताया कि वह भयानक सिरदर्द से पीड़ित थे।' कृपलानी ने विभाजन के विरुद्ध कुछ नहीं बोला था, लेकिन वह इसके विरोधी थे।

सीमांत गांधी का विरोध । उस बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्थिति बहुत अजीब रही। लोहिया लिखते हैं, 'इस बैठक के दौरान पूरे दो दिनों तक हम लोगों से ठसाठस भरे कमरे के एक कोने में एक कुर्सी पर बैठे मौलाना आजाद लगातार अबाध गति से सिगरेट का धुआं उड़ाते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले।' बैठक में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई डॉक्टर खान ने विभाजन का कड़ा विरोध किया था। वह पहले और अकेले व्यक्ति थे, जिन्होंने चीखकर प्रस्ताव को पूर्णतया अव्यावहारिक बताया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि उनके सहयोगियों ने विभाजन की योजना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जनमत गणना में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के इन दो विकल्पों के सिवा, क्या यह भी जोड़ा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत चाहे तो स्वतंत्र भी रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

बाधाओं ने दी ऊंचाई

आधी दुनिया

प्रणव प्रियदर्शी

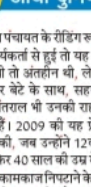

कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो अपने मुकाम से नहीं बल्कि सफर में आने वाली बाधाओं से परिभाषित होती हैं। एम अंबिका की यात्रा भी ऐसी ही रही। एक साल की उम्र में मां की ममता और 8 साल की उम्र में पिता के साये से वंचित होना तो इन कठिनाइयों की महज शुरुआत थी। रेलवे में स्वीपर का जॉब कर रही बड़ी बहन की देखरेख में अंबिका की स्कूली शिक्षा जारी रही, उसे हॉस्टल में डाल दिया गया था। लेकिन अनाथ होने का अहसास उनके किशोर मन पर ऐसा हावी हुआ कि पढ़ाई में दिलचस्पी खत्म हो गई। नतीजा, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाईं। इसके बाद 18 साल की उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई। पति की टेलिफोन बूथ और कैसेट की दुकान थी। वह जैसे-तैसे गृहस्थी जमाने में लगीं। 22 साल की उम्र में दो बच्चों की मां के रूप में उनका सामना बेटी की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से हुआ। बहरहाल, सबसे बड़ी बात यह रही कि इन तमाम चुनौतियों के बीच भी शिक्षा के प्रति बचपन में पैदा हुई ललक और वकील बनने की हसरत मन में दब भले गई हो, बुझी नहीं थी। इसलिए 2009 में जब स्थानीय पंचायत के रीडिंग रूम में उनकी मुलाकात एक साक्षरता कार्यकर्ता से हुई तो यह आग फिर सुलग उठी। बाधाओं की सूची तो अंतहीन थी, लेकिन संकल्प को सहारा मिला पति और बेटे के साथ, सहयोग, समर्थन से। आठ साल के लंबे अंतराल भी उनकी राह की बाधाओं का पुख्ता संकेत दे देते हैं। 2009 की यह प्रेरणा 2017 में जाकर तब फलित हो सकी, जब उन्होंने 12वीं के समकक्ष कोर्स में दाखिला लिया। फिर 40 साल की उम्र में लॉ डिग्री कोर्स जॉइन किया और घर के कामकाज निपटाने के बाद घर से कॉलेज के बीच डेढ़ घंटे की ट्रेन यात्रा के दौरान पढ़ाई करते हुए अब 46 साल की उम्र में उन्होंने एडवोकेट बनने का सपना आखिर साकार कर लिया।

एम अंबिका

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

स्पेस में नई पहचान

11 जून का संपादकीय 'नियति से भेंट' पढ़ा। लखनऊ में जनमे शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने वाले हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। शुभांशु के साथ 140 करोड़ भारतीयों की न केवल उम्मीदें है, बल्कि महत्वाकांक्षाएं और शुभकामनाएं भी हैं। उनकी यह यात्रा भारत के आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिहाज से भी अहम होगी। आज भारत स्पेस के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत कैसे इस क्षेत्र में प्रगति की राह पर है। यही नहीं भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO की पूरे विश्व में एक अलग पहचान बन चुकी है। दुनिया जानती है कि इस संस्थान को कम खर्च में भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में महारत हासिल है।

पैंथर तोमर, किशनगंज

डर खत्म हो

11 जून का लेख 'सरकारी लहजे का फायदा उठा रहे स्कैमर' साइबर ठगी के एक नए और खतरनाक पहलू को उजागर करता है। आखिर स्कैमर अपनी साजिश में क्यों सफल हो रहे हैं? हमारे भीतर गहराई से जमा सरकारी तंत्र का अनजाना भय उनके काम आता है। वे इसी का फायदा उठाते हैं। सिर्फ डिजिटल जागरूकता फैलाने से लोगों का यह भय दूर नहीं होने वाला। जिस डांटने वाली भाषा में सरकारी अधिकारी संवाद करते हैं, उसी भाषा का सहारा ये स्कैमर ले रहे हैं। जाहिर है, सरकार को आम लोगों से संवाद के अपने अंदाज पर गंभीरता से गौर करना होगा।

मृदुला कश्यप, गाजियाबाद

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

आज भी चिलचिलाती गर्मी, कल होगी आंधी और बारिश - एक खबर - गर्मी से राहत तो आंधी से तबाही, मौसम कूल कब से रहेगा!

पूर्णिमा रावत

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

पुरुषार्थ से बचने का बहाना है भाग्य के भरोसे बैठना

जयति गोयल

कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर हमारे भाग्य को पहले से लिख देता है और भाग्य के अनुसार ही हमें जीवन में सफलता और असफलता मिलती है। भाग्यवादी लोग कहते हैं, 'जो किस्मत में लिखा है, वही होता है - भले कर्म कुछ भी करते रहो।' कर्मवादी लोग कहते हैं, 'भाग्य कुछ नहीं होता।' भाग्यवादी और कर्मवादी लोगों की यह बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सत्य है कि भाग्य और कर्म, दोनों के बीच एक रिश्ता जरूर है। कर्म अध्ययन के समान है और भाग्य परिणाम के।

कुछ लोग कर्म प्रधान नीति से जीवन जीते हैं। वे इस बात पर अडिग विश्वास रखते हैं कि उनके जीवन में जो भी हुआ है, उसके पीछे उनके अपने कर्म हैं। दूसरे कुछ लोग भाग्य नीति से जीवन जीते हैं। उनका विश्वास अडिग होता है कि उनके जीवन में सब कुछ भाग्य के कारण ही हुआ है। कुछ लोग दोनों को मिला देते है। वे अपने आपको प्रभु को समर्पित कर देते हैं। उन्हें अपने कर्मों के बदले जो कुछ मिलता है, उसे प्रभु का प्रसाद मानकर आनंद से जीवन जीते हैं। वे सबसे ज्यादा सुखी हैं।

भारत के लगभग हर व्यक्ति की नस में भाग्यवादिता कूट-कूट कर भरी हुई है। हर आदमी का अपने कर्मों पर नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए सुखद और अच्छे होने पर ज्यादा ध्यान रहता है। पुराने समय में राजा-महाराजा भी अपने यहां राज ज्योतिष रखते थे। आज भी वही सोच कायम है। बड़े-बड़े राजनेता, अभिनेता भाग्य को जानने के लिए ऐसा करते हैं। जिन संतों ने मनुष्य को भाग्यवादिता से ऊपर उठने की प्रेरणा दी, उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छाशक्ति आपका भाग्य बनाती है।

हम अपनी इच्छा शक्ति को तब कमजोर करते हैं जब हम ऐसी गलत धारणाओं को स्थायी रूप से अपने साथ जोड़ लेते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा। यह हम अपनी अज्ञानता के कारण कहते हैं। क्योंकि हमें प्रकृति के नियमों की जानकारी नहीं होती इसलिये हम परमात्मा और भाग्य पर सब छोड़ देते हैं या उन्हें जिम्मेवार मानते हैं। भाग्यवाद और कुछ नहीं सिर्फ पुरुषार्थ से बचने का एक बहाना या आलस्य है, जो खुद अपने ही मन से गढ़ लिया जाता है। भाग्य या किस्मत ऐसे नाम हैं जिनसे सब परिचित हैं, लेकिन उसके गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। आस्था, विश्वास और इच्छाशक्ति तीन ऐसे शब्द हैं, जिन्हें मिलाया जाए तो फिर किस्मत को भी बदलना पड़ता है।

किस्मत को बदलना सिर्फ सोच को बदलने जैसा है। भगवद्गीता में कहा गया है- कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें, लक्ष्य तय करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं।

190 घंटे बिताए थे अंतरिक्ष में राकेश शर्मा ने अप्रैल, 1984 में जब वह सोवियत संघ के साझा स्पेस मिशन पर सोयूज टी- 11 से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे।

एक्सिओम-4 मिशन

राष्ट्र के लिए प्रेरक होगी यह उड़ान

अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत का परचम लहराने का इंतजार जल्द ही पूरा होने वाला है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही अपने तीन सहयात्रियों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए शुभांशु आइएसएस की उड़ान भरने वाले पहले, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। शुभांशु की उड़ान हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायक होगी

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टैली परफार्मेंसेज से संबद्ध

अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार एक्सिओम- 4 यान। इनसेट में शुभांशु शुक्ला। फाइल

बात जटिल अभियानों की हो, तो साफ है कि हर कोई उसकी योग्यता नहीं रखता। इसमें भी अंतरिक्ष से जुड़े मिशनों के लिए तो योग्यता के साथ जीवट और गहन प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। इन कसौटियों पर देखें तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन- इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी- नासा के संयुक्त मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) की राह पकड़ने वाले भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हमारे लिए नई प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। इसरो और नासा के साझा अभियान एक्सिओम-4 पर अमेरिका के स्पेस सेंटर से 14 दिवसीय मिशन पर अगर शुभांशु शुक्लस अंतरिक्ष में आइएसएस पर कामयाबी के साथ पहुंचते हैं, तो ऐसा कीर्तिमान रचने वाले वह दूसरे भारतीय होंगे। उनसे पहले यह कारनामा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वर्ष 1984 में कर चुके हैं। उनके बाद शुभांशु यदि ऐसा इतिहास रचते हैं तो उनकी यह उपलब्धि व्यक्तिगत न होकर राष्ट्र की होगी, क्योंकि इससे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका मुख्य रूप से रेखांकित होगी।

जहां तक एक्सिओम-4 मिशन का सवाल है, तो इसे लेकर दो साल पहले 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच सहमति बनी थी। इसरो के मुताबिक मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) ने अपने कार्यक्रम के लिए नासा द्वारा मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर एक्सिओम स्पेस (यूएसए) के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता (एसएफए) किया था, जिसका नाम एक्सिओम-4 है। यह भी कहा गया है कि एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट के रूप में दो गगनयात्रियों की सिफारिश की थी, जिनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (प्राइम) और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर (बैकअप) को शामिल किया गया था। शुक्ला और नायर, दोनों ही भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन- गगनयान के लिए चुने गए भारतीय वायुसेना के चार अधिकारियों में शामिल हैं, जो संभवतः अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा।

अंतरिक्ष में जाना क्यों जरूरी : विश्व में केवल तीन देश हैं जिन्होंने अब तक अपने प्रयासों से नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा है। इसमें पहली उपलब्धि सोवियत संघ (आज के रूस) के नाम है, जिसने 1957 में दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। सोवियत संघ ने 12 अप्रैल, 1961 में अपने नागरिक यूरी एलेक्सेविच गागरिन को वोस्टाक-1 नामक यान से स्पेस में भेजा था। इसके बाद से रूस वोस्टाक, वोस्खोड और सोयूज यानों से करीब 74 मानव मिशनों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसके बाद बारी आई अमेरिका की, जिसने पांच मई, 1961 को अपने नागरिक एलन बी. शेपर्ड को प्रोजेक्ट मरकरी मिशन के स्पेसक्राफ्ट फ्रीडम-7 से अंतरिक्ष में रवाना किया था। इसके बाद से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 200 से ज्यादा मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज चुकी है जिनमें से ज्यादातर का संबंध अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) से है। ऐसा करिश्मा करने वालों की सूची में तीसरा देश चीन है, जिसने 15 अक्टूबर, 2003 को अपने नागरिक यांग लिवेई को यान शिंझोऊ-5 से अंतरिक्ष में भेजा था। वैसे तो इस अवधि में कई अमीर पर्यटक भी स्पेस टूरिज्म के तहत अंतरिक्ष की सैर कर चुके हैं और संभवतः सैकड़ों लोग निजी कंपनियों की मदद से स्पेस की सैर का आनंद ले सकेंगे, लेकिन जो बात देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में जाने की है, उसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस नजरिये से देखें तो राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक होने का रुतबा हासिल है।

गगनयान से वास्तविक सफलता : असल में स्वदेशी प्रयासों से अंतरिक्ष छूने का सारा दारोमदार अब इसरो के अभियान गगनयान पर टिका है। वर्ष 2018 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि जल्द ही हमारे देश का कोई प्रतिभावान स्वदेशी अभियान की बदौलत अंतरिक्ष के भ्रमण पर होगा। यह उपलब्धि केवल उस नौजवान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि देश के लिहाज से भी इसका महत्व यह होग कि इससे भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो अपने नागरिकों को स्वदेशी तकनीकों के बल पर अंतरिक्ष में भेज सकता है। उस समय इसरो ने इस बारे में तैयारियों की अपनी योजना का राजफाश भी किया था। इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष ने बताया था कि इस महान उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे विशेष यान- गगनयान का 70 प्रतिशत काम पूरा भी हो चुका है। 2026 में गगनयान अभियान पर रवाना होगा।

साकार होगा स्पेस टूरिज्म का सपना : विश्व में स्पेस टूरिज्म और अंतरिक्ष के संसाधनों के दोहन को लेकर हो रही पहलों पर भी नजर डालना जरूरी है। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क, वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपनी कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' के अलावा जी-फोर्स वन, ब्लून, रूसी कंपनी ल्यूशिन-76 एमडीके, स्पेस एडवेंचर, प्रोजेक्ट एम-55 एक्स आदि कई निजी कंपनियों के मालिक-संस्थापक इस कोशिश में हैं कि स्पेस टूरिज्म के सपने को साकार करते हुए लोगों को अंतरिक्ष भ्रमण कराया जा सके और उसके बल पर अकूत कमाई का रास्ता खोला जा सके। इसी तरह एक मामला अंतरिक्ष की खोज और उसके (संसाधनों के) दोहन का है। अमेरिका और रूस के बाद चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मानव मिशनों को स्पेस में भेज चुका है और आगे चलकर चंद्रमा के खनिजों के दोहन की बात भी उसके जेहन में है। साथ ही, अपने राकेटों से विदेशी सेटेलाइटों के प्रक्षेपण के बाजार में भी वह सेंध लगाना चाहता है, ताकि इस मामले में भारत के इसरो की बढ़त और कमाई को कम किया जा सके।

स्पेस मार्केट में दबदबे के लिए जरूरी है कि कोई देश अंतरिक्ष के मिशनों से अपनी योग्यता व क्षमता लगातार साबित करे। भारत के लिए यह राहत की बात है कि पिछले कुछ अरसे में इसरो ने तमाम कामयाबियों से अपनी क्षमता दुनिया के सामने रखी है। इससे पूरे स्पेस मार्केट में खलबली मची हुई है। आज आलम यह है कि अंतरिक्ष अभियानों में भारत की संलिप्तता को लेकर पहले जो विकसित पश्चिमी देश उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही देश अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारतीय राकेटों का सहारा ले रहे हैं। साफ है कि आज अगर भारत इससे आगे बढ़ते हुए स्पेस में मानव मिशन की बात कर रहा है, तो उसका यह नजरिया देश को अंतरिक्ष में लंबे समय तक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का है, ताकि देश की भावी पीढ़ी को ज्ञान से लेकर रोजगार तक में उसका लाभ मिल सके।

कम खर्च में भारत की अंतरिक्ष उड़ान

इसमें संदेह नहीं कि अब तक जो उपलब्धि केवल अमेरिका, रूस और चीन हासिल कर पाए हैं, उस तक पहुंचने का एक अभिप्राय यह है कि इससे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। पर इससे ज्यादा बड़ी बात वह है, जिसका इशारा कई मौकों पर राजनेता और हमारे विज्ञानी स्वयं करते रहे हैं। जैसे कि दस साल तक इसरो के मुखिया रहे यू. आर. राव ने एक अवसर पर कहा था कि भारत को स्पेस में मानव मिशन की एक सख्त जरूरत चीन की चुनौतियों के मद्देनजर है। यानी भारत ने जल्द ही ऐसा नहीं किया तो वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की रेस में चीन से ही मात खा बैठेगा। वैसे तो अमेरिका और रूस की तुलना में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का सफर थोड़ा छोटा है। लेकिन वर्ष 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने साढ़े पांच दशक के इस सफर में जो कुछ हासिल किया है, उसने विकसित देशों को भी चमत्कृत किया है। खास तौर से खर्च के मामले में। बात चाहे चंद्रयान या मंगलयान की हो या फिर सैटेलाइट प्रक्षेपण की, इन सारे मोर्चों पर सीमित खर्च में सफलता की जो दर इसरो की रही है, वह दुनिया के अन्य अंतरिक्ष संगठनों के लिए सपना ही है। इस नजरिये से देखें तो भारत अपने मानव स्पेस मिशन से यही बात साबित करना चाहता है कि वह न केवल ऐसा करने में सक्षम है, बल्कि वह इस कामयाबी में भी मितव्ययिता की मिसाल रखना चाहता है।

यह भी ध्यान रहे कि अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन के लिए लगभग वही कसौटियां होंगी, जो दुनिया के अन्य देशों के लिए होती हैं। यानी बात केवल यह नहीं होगी कि कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचकर और उसकी देहरी छूकर फौरन वापस आ जाए और इसे कामयाबी बता दिया जाए। असल में इसरो के मानव मिशन के लिए फिलहाल तय की गई शर्तों के मुताबिक इसके लिए भारतीय एस्ट्रोनाट को कम से कम सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहना होगा। इसके लिए बनाए जाने वाले अंतरिक्ष यान गगनयान में उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्री का चयन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा और उन्हें स्पेस फ्लाइट की ट्रेनिंग विदेश में दी जाएगी। इस अभियान की कुछ अहम शर्तें और हैं। जैसे, इस योजना को सिरे चढ़ाने से पहले मिशन में इस्तेमाल होने वाले राकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल मार्क-3 से कम से कम दो मानवरहित उड़ानें कराना अनिवार्य है। इसमें जरूरी यह है कि मार्क-3 पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण होगा। इसरो के मुताबिक वह इसकी कुछ टेक्नोलाजी विकसित कर चुका है। जैसे इसरो ने पहले ही क्रू माड्यूल और स्केप सिस्टम का परीक्षण कर लिया है। शेष तैयारियां अगले कुछ चरणों में पूरी हो जाएंगी। इसरो ने मंगलयान के अलावा अपने राकेटों में भारी विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके जो प्रतिष्ठा हासिल की है, उसे देखते हुए गगनयान से किसी भारतीय को स्पेस में भेजने का उसका सपना असंभव नहीं लगता है।

(अभिषेक कुमार सिंह)

खरी-खरी

बधाई का बाजार

सुनील जैन राही

किसी की खुशी में शामिल होना बहुत मुश्किल है। किसी को खुश देख कर खुश होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरे की खुशी देखकर अक्सर मन कुढ़ जाता है। हर इंसान सफल कलाकार है। मन में कटि-छुरियां चल रही हों, लेकिन सामने वाला समझता है, हमसे ज्यादा इसे खुशी मिली है।

बहरहाल... इतनी खुशी मिली कैसे? काश हमें भी मिलती? दूसरे की खुशी में शामिल होना मजबूरी है। हम अपनी सफलता पर खुश होते हैं, दूसरे की सफलता पर खुश तब होते हैं, जब उसकी सफलता हमसे कम हो।

बात बधाई की है। बधाई का बाजार बढ़ गया है। जब आत्मीयता कम और औपचारिकता अधिक हो तो बधाई अनौपचारिक नहीं रह जाती है। बधाई रिश्तों की मोहताज हो गई है। वैचारिक/ धार्मिक/ राजनीतिक दृष्टिकोण बधाई के तूफान लाते हैं। जैसा रिश्ता, वैसी बधाई।

बधाइयों के बाजार में कई बधाई उपलब्ध हैं। लड्डू वाली, काजू कतली वाली, डिनर वाली, जन्म दिन की। बधाई सफलता का पैमाना है। जितनी बड़ी बधाई, उतनी बड़ी सफलता। लाइक और कमेंट ने बधाई को कमतर कर दिया है। बधाई सफलता देखकर नहीं, व्यक्ति और संबंध देखकर दी जाती है। बधाई के कई कारण हैं- स्थिति/ रिश्ते/ पद/ समय और मिलने वाले लाभ पर निर्भर करता है। निर्मल प्यार की तरह बधाई निर्मल नहीं होती। निरपेक्ष बधाई में अक्सर लोग स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। इस महंगाई के जमाने में बधाई जैसी महंगी वस्तु देना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब हमें नहीं मिली तो तुम्हें कहां से दें?

बधाई में समूह का अस्तित्व। समूह विचारों पर निर्भर होता है। इसमें आने वाली बधाई समूह के विचार से मेल खाती है। अगर समूह से विचार मेल नहीं खाते तो बधाई शून्य बटा सन्नाटा है। आजकल विभिन्न विचारों के समूह बने हुए हैं। आप किस समूह को बिलांग करते हैं, उसी समूह के लिए बधाई के पात्र हैं। जरूरी नहीं कि अधिक बधाई पाने वाला श्रेष्ठ हो? हो सकता है वह श्रेष्ठ समूह से संबंध रखता हो? साहित्य में जो अंकुरित हो रहे हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। बधाई में कमी, पुरस्कार के लिए दुखदायक है।

X पोस्ट

कांग्रेस चाहती तो वह पूरी महफिल लूट सकती थी। उसे बस इतना करना था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले ही वह अपने उन चार नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस करा देती, जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने थे, लेकिन पार्टी के रवैये को लेकर क्या ही कहा जाए....

पल्लवी घोष@_pallavighosh

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक परीक्षा का छह महीनों में फिर से 'अपरिहार्य कारणों' से स्थगित होना चौंकाता है। इससे युवाओं में निराशा और आक्रोश बढ़ता है। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी तय की जाए। वे अफसर हटाए जाएं, जो सिर्फ स्थगन-स्थगन खेलते हैं।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

ऐतिहासिक अर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी निमंत्रण दर्शाता है कि अमेरिका-यूरोप से सौदा किया जा सकता है, भरोसा नहीं। इस निमंत्रण के पहले अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता दिख रहा था, पर उसका असली चेहरा उजागर हो गया है।

मधुरेंद्र कुमार@Madhurendra13

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या लास एंजिलिस हिंसा अमेरिका में भी ट्रंप की छवि खराब कर सकती है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आपरेशन सिंदूर के बाद विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडल अपने उद्देश्य में सफल रहे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

टेढ़ा आंगन लग रहा किंतु न आवे नाच,
हर चुनाव की चाहिए इनको केवल जांच।
इनको केवल जांच स्वयं जब जीते भाई,
तब ईवीएम भूल बजाते ये शहनाई।
बदलो शैली आप और बदलो अपना मन,
तभी नाचने योग्य बनेगा टेढ़ा आंगन!

- ओमप्रकाश तिवारी

संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश डायरी

व्यापमं का नाम बदला, परंतु कदाचार यथावत

वर्षों पहले मध्य प्रदेश के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश परीक्षा एवं बाद में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने के लिए बने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने सरकार की साख पर ऐसा दाग लगाया जो अब तक नहीं छूटा है। वर्ष 2013 में जब यह राज खुला कि व्यापमं में बैठे अफसरों ने सत्ता में बैठे लोगों से साठगांठ कर अयोग्य लोगों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिलवा दिया और उनकी साठगांठ से अयोग्य लोग नौकरी पा गए हैं तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। राज्य सरकार कठघरे में थी। शुरुआती ना-नुकुर के बाद राज्य सरकार ने इन आरोपों-शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी एटीएस को दी। लंबी जांच के बाद तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापमं के अधिकारी पंकज त्रिवेदी, नितिन महेंद्र, सीके मिश्रा आदि को कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में सीबीआइ ने जांच शुरू की। उसने भी कई लोगों की गिरफ्तारी की। कई निजी मेडिकल कालेजों के संचालक, साल्वर, विद्यार्थी और बिचौलिए पकड़ में आए। इसी दौरान मामले में आरोपित कई लोगों की मौतों का सिलसिला भी शुरू हुआ। इन मौतों की खूब चर्चाएं हुईं। बाद में आरोपितों में से अनेक लोग जेल से बाहर भी आ गए।

समय के साथ नेताओं-अधिकारियों से संबंधित केस की चर्चाएं कम हुईं, लेकिन व्यापमं का भ्रष्टाचार सरकार से इस कदर नत्थी हुआ कि लाख प्रयास के बावजूद अलग नहीं हो पा रहा था। चुनाव नजदीक आता देख सरकार ने व्यापमं का नाम बदलकर पीईबी अर्थात प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। नाम बदलने से सरकार को उम्मीद थी कि शायद व्यापमं के दाग धुल जाएंगे, लेकिन ये दाग इतने गहरे थे कि लोगों के जेहन से नहीं निकले। असर यह हुआ कि 2018 में विधानसभा का चुनाव भाजपा हार गई। 15 महीने बाद अचानक जोड़-तोड़ करके भाजपा सत्ता में वापस आ गई। सरकार बनते ही प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) कर दिया गया। कोशिश थी कि व्यापमं घोटाले का दाग इस नाम के साथ धुल जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। स्थिति यह है कि व्यापमं के भ्रष्टाचार का डीएनए ईएसबी की कार्यसंस्कृति में भी समाहित हो गया है। नाम बदलने के बाद भी हर परीक्षा पर व्यापमं की छाप दिखती है। अंतर केवल इतना आया है कि परीक्षा में धांधली का तरीका अधिक तकनीकी और जटिल हो गया है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल : नाम बदला लेकिन फर्जीवाड़े का चरित्र कायम रहा। फाइल

फिलहाल कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 2023 में कराई गई पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में व्यापमं जैसा ही फर्जीवाड़ा चर्चा में है। अगस्त-सितंबर 2023 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। सात मार्च 2024 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। अब सामने आ रहा है कि इस परीक्षा के दौरान अनेक अभ्यर्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाए गए और उन्हें पास कराया गया। ऐसे लोगों का अंतिम सूची में चयन भी हो गया। अप्रैल-मई 2025 में जब अलग-अलग जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होने लगा तो ग्वालियर में पहली बार पांच मुन्नाभाई पकड़ में आए। मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर निवासी पांच लोगों ने लिखित परीक्षा से ठीक पहले अपना आधार अपडेट कराया था। इस अपडेशन के जरिये फोटो और बायोमीट्रिक चिह्न बदला गया था। परीक्षा के तुरंत बाद आधार का यही डाटा फिर से बदलवाकर पुराना वाला कर दिया गया।

कुछ दिनों बाद ही राजगढ़ में एक नया चयनित सिपाही इसी तरह के फर्जीवाड़े में पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि आधार का रिकार्ड बदलकर सत्येंद्र सिंह जादौन की जगह ग्वालियर के सतेंद्र रावत ने परीक्षा दी थी। पुलिस का कहना है कि वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे रही है और आधार प्राधिकरण को अपडेशन किए जाने के प्रक्रिया की उस खामी के बारे में लिखा गया है, जिसका फायदा उठाकर जालसाजों ने परीक्षा में सेंध लगाई। हालांकि सरकारी जांच एजेंसियां इसमें कर्मचारी चयन मंडल की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हैं। सवाल तो ईएसबी की व्यवस्था पर ही सबसे अधिक उठ रहे हैं।

ये सवाल अकारण भी नहीं हैं। इससे पहले 2023 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया था। उस समय पता चला था कि परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान पर आए सात अभ्यर्थी ग्वालियर के एक ही केंद्र पर परीक्षा में शामिल हुए थे। इस केंद्र से कुल 114 परीक्षार्थियों का नाम सफलता पाने वालों की सूची में था। यह केंद्र एक भाजपा नेता के कालेज में बना था। हंगामा मचा तो जांच भी घोषणा हुई। परिणाम रोक दिए गए, लेकिन साठगांठ की कोई गंभीर जांच नहीं हुई। परीक्षा कराने वाली यह संस्था हर परीक्षा में स्वयं सवालों से घिरी रहती है। समय पर परीक्षाएं नहीं हो पा रहीं, जो परीक्षाएं हो रहीं उनमें विवाद खड़े हुए हैं। ऐसे ही फर्जीवाड़े के कारण उसके परिणाम रुके हुए हैं। सच यह है कि व्यापमं का डीएनए ईएसबी के साथ खेल कर रहा है, क्योंकि नाम बदला है, लेकिन संस्थागत फर्जीवाड़े का चरित्र वैसे ही है।

हिमाचल प्रदेश डायरी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

निशुल्क कुछ नहीं होता!

हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पर्ची के पैसे लगेंगे। यह इस पर्वतीय प्रदेश की वह खबर है जो बीते सप्ताह चर्चा में रही। क्योंकि विषय, राजनीतिकों को छोड़ सबकी सेहत से जुड़ा है, इसलिए सोशल चैटर पर भरपूर प्रतिक्रियाएं आईं। समाज के हर व्यक्ति की अपनी राय थी। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले तीन अलग-अलग अनुभव देखिए।

एक सरकारी अस्पताल में एक जानकार ने मुस्कुराते हुए डाक्टर साहब के आगे पांच पर्चियां रख दीं। डाक्टर साहब ने पूछा, 'यह क्या है?' जवाब मिला, 'आज हम सबका अवकाश था, कई दिन से घुटने नहीं देखे अपने, समस्या कोई नहीं, बस देखना है कि अंदर से कैसे हैं। आप एक्स-रे और बाकी टेस्ट लिख दीजिए।'

मुख्यमंत्री कह रहे थे, 'कई अस्पताल रैफरल यूनिट बन गए हैं, टांडा मेडिकल कालेज में साधारण स्कैनिंग के लिए भी चार माह की वेटिंग है। आइजीएमसी में 19 साल पुरानी मशीनों से काम चलाया जा रहा है। यह सब भाजपा के कुप्रबंधन के कारण हुआ।'

नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं, 'जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुख की अनुभूति होती है। आज चुनाव हो जाए तो भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने टैक्स लगाने पर जोर दिया है।' इसके अतिरिक्त एक जानकार का कहना था कि पर्ची पर शुल्क संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

राजनीति का ध्येय ही अपने मत का प्रचार इस प्रकार करना है कि प्रतिद्वंद्वी का आख्यान पिट जाए। इसमें स्वास्थ्य की चिंता किसे कितनी है, वह लक्ष्य नहीं होता। कैसे? पर्ची शुल्क दस रुपये है। वह भी मुख्यमंत्री का कहना है कि रोगी कल्याण समितियों पर छोड़ा है कि लेना है अथवा नहीं। पहले रोगी कल्याण समितियां यूजर चार्ज लेती रही हैं। उससे यह होता था कि स्वास्थ्य संस्थान के प्लंबर, कारपेंटर, पेंटर आदि से जुड़े छोटे, किंतु बड़े कार्यों के लिए सरकार की ओर नहीं देखना पड़ता था। किसी पात्र रोगी के लिए अकस्मात दवा की आवश्यकता भी पूरी हो जाती थी। अब दवाएं ही नहीं हैं। टांडा में कैथ लैब कभी भी बंद हो सकती है। पर्ची कार्ड की तरह हो, पूरा रिकार्ड हो, डाक्टर को ओपीडी की जानकारी हो, फालोअप के लिए जगह हो तो बुरा क्या है। निशुल्क कुछ नहीं होता। न पानी, न बिजली न कोई और संसाधन। सवाल यह भी उठता है जो 1500 रुपये चाहने वाले लोग दस रुपये नहीं दे सकेंगे?

दूसरा, सरकारें कोई भी हों, आज तक संख्या पर तो ध्यान दिया गया, गुणवत्ता पर नहीं। कोरोना काल में वेंटीलेटर कम थे, जब आए तो चलाने वाले नहीं थे। आज भी संभवतः सब डिब्बों में बंद पड़े होंगे। पर्ची शुल्क इसलिए भी होना चाहिए कि निशुल्क की संस्कृति ने जनमानस को राजनीतिक दलों के साथ मोलभाव की स्थिति में ला दिया है। चुनाव के समय निशुल्क बांटने की प्रतियोगिता उस लकीर को भी मिटा देती है जहां राज्य के कल्याणकारी दायित्व और आत्मनिर्भरता में अंतर समझा जाता है। जो अधिक निशुल्क का वादा भर कर दे, जनमानस उसका।

जनता उस स्थिति में आ गई है, जहां मांगना अधिकार है, किंतु प्रदेश, देश को कुछ देना कर्तव्य में भी शामिल नहीं? ऐसा इसलिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की प्राथमिकता बैठक में मांग आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की होती है, वहां उचित उपकरणों या चिकित्सकों की पूरी संख्या की नहीं। क्योंकि राजनीतिक जानते हैं कि घोषणाभर से बांछें खिल जाएंगी, इसी के योग्य जनता है। शिक्षा क्षेत्र में स्कूल खोलना मांग है, चाहे बोर्ड ही लगा दें। अच्छा राजनीतिक दल उसे क्यों माना जाए जो लैपटाप या साइकिल का वादा करे, उसे क्यों नहीं जो यह कहे कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम होंगे, परिसर अच्छा होगा, अध्यापक संख्या आदर्श होगी, बच्चों को हर सुविधा मिलेगी?

शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पर्ची बनवाने के लिए लगी कतार। जागरण

पिछले दरवाजे से हुई नियुक्तियों वाले धीरे-धीरे वे सब कुछ मांगते हैं जो परीक्षाएं उत्तीर्ण कर आए लोगों को मिलता है। क्योंकि पता है, मतदाता, मतदाता से अधिक अपने लालच के आगे हारने वाला एक दबाव समूह भर रह गया है। हिमाचल प्रदेश में आज भी पंजाब या उत्तराखंड से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। क्या सबमें डाक्टर या सुविधाएं हैं? हिमाचल प्रदेश के इतने मेडिकल कालेज हैं, क्यों टांडा या शिमला के ही डाक्टर भारतीय चिकित्सा परिषद के दौरे से पहले हर स्थान पर प्रदेश की लाज बचाने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाते हैं?

यह सब इसलिए, क्योंकि राजनीतिक दलों ने बड़ी मेहनत से निशुल्क की संस्कृति विकसित की है। ऐसे में, पर्ची का पच्चीस पैसे से एक रुपया होना जितना कष्टकारी शांता कुमार के मुख्यमंत्री रहते तब के प्रतिपक्ष को प्रतीत हुआ था, उतना ही कष्टकारी 2025 में दस रुपये होना आज के प्रतिपक्ष को हो रहा है। दल कोई भी हो, प्रतिपक्ष में रहते हुए आलोचना ही उसका कर्तव्य है। लेकिन निशुल्क संस्कृति से मत तो मिलते हैं, प्रदेश पीछे और देश पीछे चला जाता है। इतना पीछे कि कटोरा हाथ से छूटता ही नहीं।

****

दैनिक जागरण

मर्यादा व्यक्तित्व का आभूषण है

न्यायिक सक्रियता की अति

यह अच्छा है कि बीआर गवई जबसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तबसे वह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो संविधान की महत्ता के साथ सरकारी तंत्र और न्यायिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता रेखांकित करते हैं। आवश्यक केवल यह नहीं है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों को निर्वहन सही ढंग से करें और जनाकांक्षाओं को समझें। आवश्यक यह भी है कि न्यायपालिका भी देश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता कई बार न्यायिक अति में बदलती दिखती है। कुछ वर्ष पहले खेती और किसानों की भलाई के लिए लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों की समीक्षा किए बिना उनके अमल पर रोक लगा दी थी। संसद से बने किसी कानून पर रोक तो उसकी संवैधानिकता को परख करने के बाद ही लगनी चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इससे कृषि कानून विरोधियों के बीच यह संदेश गया कि इन कानूनों में कोई खोट है और वे सड़कों पर धरना-प्रदर्शन करते रहे। इसके चलते मोदी सरकार न चाहते हुए भी इन कानूनों को वापस लेने को बाध्य हुई। इससे किसानों और विशेष रूप से छोटे किसानों का अहित ही हुआ। इस मामले में एक खराब बात यह भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अध्ययन के लिए अपनी ओर से किसान नेताओं एवं कृषि विशेषज्ञों की जो समिति गठित की, उसकी रपट का संज्ञान ही नहीं लिया।

वास्तव में ऐसे कई मामले हैं, जब यह प्रतीत हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायिक सक्रियता के नाम पर अपनी सीमा लांघी। पिछले कुछ समय से तो संसद से किसी विधेयक के पारित होते और उसके कानून का रूप लेते ही उसके खिलाफ याचिकाएं दायर हो जाती हैं और उन पर तुरंत सुनवाई भी शुरू हो जाती है। वक्फ संशोधन कानून के साथ ऐसा ही हुआ। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को संसद की ओर से बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता जांचने का अधिकार है, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं कि प्रत्येक कानून लागू होने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाए और उसकी तत्काल सुनवाई भी होने लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामले वर्षों से लंबित हैं। इसी तरह उच्च न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। निचली अदालतों की स्थिति तो और भी खराब है। एक तथ्य यह भी है कि कोलेजियम सिस्टम में सुधार की कोई पहल नहीं हो रही है। इसके चलते उच्चतर न्यायपालिका के जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। किसी अन्य बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। यह व्यवस्था संविधानसम्मत भी नहीं है।

सशक्त होंगे किसान

झारखंड सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सचेत प्रतीत हो रही है। चाहे आपदा में किसानों की फसल को नुकसान पर मदद देने का मामला हो या उनकी आय बढ़ाने के लिए गोवंशियों को पालने में सब्सिडी देने की योजना। इसके अलावा कृषि भूमि की सिंचाई सोलर पंप से कराने को भी सरकार किसानों को मदद दे रही है। कृषि उपज खराब न हो, इसके लिए बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। इसी क्रम में जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के सालुका में 5000 मीट्रिक टन की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन हुआ है, जो किसानों को उनकी फसल औने-पौने में बेचने की मजबूरी से निजात दिलाएगा। पलामू, गढ़वा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा में 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निविदा हुई थी। इसी कड़ी में जामताड़ा में कोल्ड स्टोरेज बन चुका है। कोल्ड स्टोरेज से किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मांग कम होगी या दाम कम होंगे तो वे अपनी फसल को वहां रख सकते हैं। जरूरत पर उसे निकालकर बाजार में भेज सकते हैं। इससे उनकी आय बढ़ना स्वाभाविक है। खास बात यह कि जिस इलाके में कोल्ड स्टोरेज शुरू हुआ, वहां बिजली संकट भी था, पर विद्युत सब स्टेशन बनाकर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।

कोल्ड स्टोरेज से किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मांग कम होगी या दाम कम होंगे तो वे अपनी फसल को वहां रख सकते हैं

राष्ट्रहित पर राजनीति का रवैया

ए. सूर्यप्रकाश

राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता थरूर, खुर्शीद, कनिमोरी, ओवैसी आदि से सीखें कि जब राष्ट्रहित की बात आए तो नेताओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वैश्विक मंचों पर अपना पक्ष रखने लिए मोदी सरकार ने सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को अलग-अलग देशों में भेजने की जो पहल की, वह अपने मूल उद्देश्य से भी कहीं अधिक सफल साबित हुई है। इन प्रतिनिधिमंडलों में गए सदस्यों ने न केवल पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि आंतरिक स्तर पर कुछ विवादों-विभाजनों के बावजूद भारत मूल रूप से एक है। इन प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की समावेशी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसकी सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति तब देखने को मिली, जब द्रमुक सांसद कनिमोरी के समक्ष स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा का सवाल पूछकर उन्हें असहज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने जिस सहजता से इसका जवाब दिया कि 'विविधता में एकता' ही भारत की राष्ट्रीय भाषा है, उससे स्वाभाविक है कि किसी खास मंशा से ऐसा सवाल पूछने वालों की बोलती बंद हो गई। उल्लेखनीय है कि कनिमोरी उस तमिलनाडु राज्य से आती हैं, जहां भाषा विशेषकर हिंदी को लेकर अक्सर विवाद छेड़ दिया जाता है। यहां तक कि उनकी पार्टी अपने संस्थापक अन्नादुरई के दौर से तमिलनाडु पर 'हिंदी थोपने' का शोर मचाती रही है। यह सिलसिला जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेन्द्र मोदी की सरकारों तक कायम है। कनिमोरी ने भाषा को लेकर अपने जवाब से यही रेखांकित किया कि किसी भी सूरत में राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। यह बात अलग है कि जब स्पेन की धरती पर वह भारत की धाक जमा रही थीं तो उसी दौरान उनकी पार्टी के सहयोगी और प्रख्यात अभिनेता-फिल्मकार कमल हासन कन्नड़ भाषा को कमतर बताने और तमिल की श्रेष्ठता जताने का शिगूफा छेड़कर विवाद खड़ा करने में लगे थे।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इस मोर्चे पर सराहनीय काम किया। इसमें कांग्रेस के भी कुछ सांसद खास तौर पर शामिल हैं। अपने नेता राहुल गांधी के निरंतर शिकायती लहजे और सामान्य तौर पर नकारात्मक रवैये के बावजूद कांग्रेस सांसदों ने यही दर्शाया कि भारत राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस के ऐसे सांसदों में शशि थरूर की खूब सराहना हुई। विषय के प्रति अपने विशद ज्ञान एवं उत्कृष्ट संवाद शैली के जरिये उन्होंने अनुकरणीय रूप से भारत का पक्ष रखा। दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजने संबंधी पहल को लेकर थरूर ने मोदी सरकार को भी सराहा। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्र संकट में हो तो सभी नागरिकों का दायित्व है कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। राजनीति को इससे अलग रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार अमेरिका और मध्य अमेरिकी देशों में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए उनका चयन उनके लिए गर्व की अनुभूति कराने वाला रहा। पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी अपने दायित्व को बखूबी निभाया। उन्होंने आपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए सैन्य बलों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संवाद-सहयोग के चाहे जो प्रयास किए जाएं, लेकिन इस पड़ोसी देश की उन्हें लेकर एक ही प्रतिक्रिया होती है और वह है आतंकवाद। आपरेशन सिंदूर की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों और यहां तक कि अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी खुर्शीद ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी मोदी सरकार के फैसले का पुरजोर समर्थन किया। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें निशाना बनाया, जिसकी पीड़ा उन्होंने यह कहकर व्यक्त की कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है। थरूर और खुर्शीद के अलावा आनंद शर्मा कांग्रेस के एक अन्य बड़े नेता रहे, जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल संबंधी कवायद को सराहा। आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका को दुनिया के सामने उजागर करने के मोदी सरकार के इस प्रयास को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। मनीष तिवारी का नाम भी उन नेताओं में जुड़ गया जिन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति कोई भी जिम्मेदारी हर चीज से ऊपर है।

पहलगाम हमले के बाद से लेकर प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी तक एआइएमआइएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का भी एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उभार देखने को मिला। उन्होंने बहुत बेबाकी से यह बात रखी कि पाकिस्तान की आतंकपरस्त नीतियों की भारत किस तरह कीमत चुका रहा है। उन्होंने अपनी विशेष भाषा-शैली और उदाहरणों के जरिये दुनिया का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा। उन्हें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे उन मुस्लिम देशों में गए प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा गया था, जहां पाकिस्तान अक्सर मजहबी दुहाई देता रहता है। उनके प्रतिनिधिमंडल ने मुखरता से इस पहलू को रेखांकित किया कि पाकिस्तानी आतंकवादी अपनी गतिविधियों से भारत के बहुलतावादी, उदार एवं लोकतांत्रिक समाज के तानेबाने को छिन्न-भिन्न करना चाहते थे। विभिन्न दलों के सांसदों एवं विशेषज्ञों को दुनिया भर में भेजने के मोदी सरकार के इस प्रयास की व्यापक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। इस संदर्भ में कनिमोरी के भारत की भाषा संबंधी बयान की बात करें तो यह केवल देश की भाषाई विविधता से ही नहीं जुड़ा था। ध्यान रहे कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं भाषाई विविधता वास्तव में बेजोड़ है।

भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ही नहीं, बल्कि सर्वाधिक विविधतापूर्ण एवं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है। हमारे संविधान में धार्मिक, भाषाई एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए जिस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनकी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती। राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को कनिमोरी एवं दूसरे सांसदों से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रहित की बात आए तो अपना रवैया कैसा रखना होता है। राहुल गांधी यह भी सीख लें कि विदेशियों या अन्य देशों के नेताओं के समक्ष खुद को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

वैवाहिक संबंधों में विश्वास का खात्मा

क्षमा शर्मा

यदि अपनों का ही विश्वास न रहे तो आखिर हम इस दुनिया में किस पर भरोसा कर सकते हैं?

पति को मारकर उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट से ढकने वाली मेरठ की मुस्कान का केस ठंडा भी नहीं हुआ था कि इंदौर की सोनम का मामला सामने आ गया। कौन अपराधी है और कौन नहीं, अदालत किसे कितनी सजा देगी, यह वक्त बताएगा, लेकिन यह सोचकर दहशत होती है कि हनीमून के लिए मेघालय गई सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया। ससुराल वालों के साथ खुश रहना, विवाह के समय नाचना-कूदना और मन में किसी और योजना का चलना। क्या सचमुच उसने राज कुशवाहा जैसे फटेहाल प्रेमी के लिए यह सब किया या किसी और के लिए? राजा की हत्या का राज खुलने के बाद कुछ लोग एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं कि 90 प्रतिशत से अधिक अपराध पुरुष करते हैं और स्त्रियां तो मात्र छह-आठ प्रतिशत ही ऐसा करती हैं। क्या यह कहा जा रहा है कि जब तक 92-94 प्रतिशत स्त्रियां भी अपराध न करने लगें, तब तक इन घटनाओं की अनदेखी की जाए?

अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए। स्त्री-पुरुष नहीं करना चाहिए। इसीलिए लंबे अर्से से मांग हो रही है कि स्त्रियों संबंधी कानूनों को लैंगिक भेद से मुक्त किया जाए। स्त्री या पुरुष, जो भी अपराधी हो, उसे सजा मिले। कई महिलाएं टीवी डिबेट्स में कह रही हैं कि सोनम का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जबकि वह राजा के घर वालों से बात कर रहा है तो सोनम और राज कुशवाहा के घर वालों से भी। जब किसी पुरुष के आरोपित बनते ही उसके परिवार वालों को रात-दिन दिखाया जाता है, तब ऐसे विचार क्यों प्रस्फुटित नहीं होते? दुष्कर्म के मामलों में महिलाओं के तो नाम बताना, चित्र दिखाना अपराध है, लेकिन पुरुषों के चित्र हर वक्त दिखाए जाते हैं। अगर वे निर्दोष साबित हो जाते हैं तो क्या उनकी और उनके परिवार की खोई प्रतिष्ठा वापस मिलती है? अनेक बार तो नौकरी तक चली जाती है।

इस प्रसंग में 1988 का चर्चित इंदु अरोड़ा-अजीत सेठ कांड याद आता है। हरीश से विवाहित इंदु के अजीत से संबंध थे। उन्हें लगता था कि उनके संबंधों में इंदु के दो छोटे बच्चे रोड़ा बन रहे हैं। दोनों ने मिलकर बच्चों पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। उस समय इस घटना पर भी लोगों में काफी आक्रोश जागा। जब उन्हें जेल भेजा गया तो वहां कैदियों ने उनकी पिटाई की।

पति राजा रघुवंशी की हत्या कराने वाली सोनम। प्रेट्र

मेघालय की घटना से राजा रघुवंशी और सोनम के साथ उन चार लड़कों के परिवार भी तबाह हुए, जिन्हें हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। जो किसी अपराध को अंजाम देते हैं, उन्हें यह क्यों नहीं लगता कि वे पकड़े भी जाएंगे या यह सोचते हैं कि कुछ भी करके बच निकलेंगे? पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एकम न्याय फाउंडेशन की दीपिका भारद्वाज ने दो फिल्में बनाई हैं-मार्टरस आफ मैरिज और इंडियाज संस। वह पुरुष आयोग बनाने की मांग करती रही हैं। उन्होंने पत्नियों द्वारा पति की हत्या और पुरुषों की आत्महत्या के मामलों का अध्ययन किया था। इसके अनुसार देश भर में जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर तक 306 पतियों और कई मामलों में उनके परिवार वालों की हत्या पत्नियों द्वारा की गई। इनमें से कुछ हत्याओं को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई।

एक तरफ महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत सशक्त हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई स्त्री अपराध करती है, उसके बचाव में कहा जाने लगता है कि वह तो ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? आखिर वे स्त्रियां कौन हैं, जो जघन्य अपराध कर रही हैं? कई बार सोचती हूं कि किसी अपराध को साबित करने के लिए पुलिस के सामने भी कितनी चुनौतियां होती हैं। राजा की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस को आलोचना का सामना करना पड़ा। वह जिस तरह बिना किसी प्रतिक्रिया के मामले की छानबीन करती रही, वह तारीफ के काबिल है। प्रतिक्रिया न देने पर सोनम और राजा के परिवार वाले उसकी लगातार आलोचना कर रहे थे। मेघालय में ऐसे अपराध न के बराबर होते हैं। वहां भी इस घटना पर लोगों में गुस्सा है। लोग दोनों परिवारों से माफी की मांग कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर को बेवजह बदनाम किया गया। लोग पूछ रहे हैं कि यदि सोनम को राजा पसंद ही नहीं था तो उससे विवाह क्यों किया? यदि उसे इसकी चिंता थी कि मना करेगी तो हृदय रोगी पिता का क्या होगा, तो क्या अब वह बहुत खुश होंगे? वह नाते-रिश्तेदारों, आसपास वालों का सामना कैसे कर रहे होंगे? आखिर हमारे समाज में भरोसे में इतनी कमी (ट्रस्ट डेफिसिट) कैसे हो गई।

इन दिनों आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया। पत्नी ने पति को तरबूज में जहर मिलाकर खिला दिया। बेटी ने प्रेमी के लिए पूरे परिवार को मार डाला। पिता ने दूसरी शादी करने के लिए बच्चों का गला घोंटा। यदि अपनों का ही विश्वास न रहे तो आखिर हम दुनिया में किसका भरोसा कर सकते हैं। क्या यह कहने से समस्या हल हो सकती है कि विवाह संस्था सड़-गल चुकी है और अब इससे निजात पा लेनी चाहिए। पा लीजिए, लेकिन पति को पार्टनर कहने भर से स्थितियां नहीं बदल जातीं। कोई भी संबंध हो, उसमें विश्वास और धैर्य ही काम आते हैं, जिनका लगातार लोप हो रहा है।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

रिश्तों का महत्व

रिश्ते जीवन को अर्थ और पहचान देते हैं। जीवन यात्रा में मधुरिम रिश्तों का होना सुखद बयार की भांति हो सकता है, यदि वे आंतरिक भावों से पोषित और संप्रेषित किए जाते रहें। रिश्तों का अंकुरण प्रेम से होता है, वे जिंदा रहते हैं संवाद से और महसूस होते हैं संवेदनाओं से। रिश्तों का दिल से और दोनों ओर से निभाया जाना अनिवार्य पहलू है, क्योंकि ये डोर होती महीन है, किंतु इसके बंधन को सुदृढ़ बनाते हुए जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण कारक बनाया जा सकता है, जो हमें खुशी, आराम, समर्थन और सुरक्षा प्रदान कर सके। आपसी प्यार, सम्मान और विश्वास के रसायन से रिश्तों को सुमधुर बनाया जा सकता है। इससे परायों को भी अपना बनाया जा सकता है, नहीं तो अपनों को भी पराये होते किंचित देर नहीं लगती। रिश्तों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है।

रिश्तों में अपनापन हर कोई दिखाता है, किंतु सच में अपना कौन है, यह वक्त बताता है। लोगों का बदलना, रिश्तों का बदलना, मौसम का बदलना चाहे दिखाई नहीं दें, मगर ये बदलाव महसूस हो ही जाते हैं। रिश्ते मोमबत्तियों की मानिंद होते हैं, जो जीवन को प्रकाश देते हैं। अगर अनदेखी हुई तो ये पिघलकर समाप्त हो जाते हैं और पीछे केवल खालीपन छोड़ जाते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को समय देते रहना और उनकी कद्र करते रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें खो देने के बाद बस पछतावा बचा रहेगा। अहं, वहम के साथ स्वयं का स्वार्थ परख हो जाना रिश्तों के दरकने की असल वजह होती है। कहीं-कहीं देखकर लगता है कि फासले इस कदर हैं आजकल के रिश्तों में जैसे कोई घर खरीदा हो किस्तों में। रिश्तों और रास्तों में साम्यता यही है कि दोनों तब समाप्त जाते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मर्यादित आचरण की लक्ष्मण रेखा हर रिश्ते में खिंची होनी चाहिए।

एसएन दुबे 'स्नेही'

सामाजिक प्रगति में बाधक बाल श्रम

प्रो. रिपुदमन सिंह

बाल श्रम एक ऐसी समस्या है, जो बच्चों से उनका बचपन, सम्मान और संभावनाएं छीन लेती है

प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दुनिया भर में बाल श्रम की समाप्ति के लिए चलाए जा रहे सतत संघर्ष की एक सशक्त स्मृति है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में स्थापित यह दिवस बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। यह दिवस हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि तकनीक विकास और वैश्वीकरण के इस युग में भी करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने को विवश क्यों हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आज भी 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्व भर में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहा है। यह स्थिति विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे उस अंधकार को उजागर करती है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं।

बाल श्रम एक ऐसा कार्य है, जो बच्चों से उनका बचपन, सम्मान और संभावनाएं छीन लेता है तथा उनके शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को बाधित करता है। बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है तथा जो बच्चे पढ़-लिख कर अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं, उन्हें अंधकारमय भविष्य की ओर ढकेलता है। बाल श्रम के मूल में गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन है। जब एक परिवार की रोजी-रोटी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तब उनके सामने सबसे आसान विकल्प बच्चों को काम पर भेजना बन जाता है। यही कारण है कि खेतों, कारखानों, ईंट-भट्ठों, घरेलू कामकाज और निर्माण स्थलों पर मासूम बच्चे काम करते नजर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी झुग्गियों तथा प्रवासी मजदूर परिवारों में यह समस्या गंभीर बनी हुई है। इस गंभीर सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए ठोस प्रतिबद्धता की महती आवश्यकता है। बाल श्रम भारत के साथ-साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। बाल श्रम को जड़ से उखाड़ना हमारे लिए एक चुनौती है, जिस पर खरा उतरना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा एक माध्यम हो सकती है, जो किसी भी बच्चे को श्रम के कुचक्र से बाहर निकाल सकती है। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जैसे प्रयास सराहनीय हैं, पर बाल श्रम को खत्म करने के लिए इन्हें और व्यापक बनाकर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना होगा। उप्र सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून, 2025 से एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य 2027 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाना है। यह अभियान शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रम आदि विभागों की भागीदारी से संचालित होगा।

(लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एवं पूर्व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी हैं)

विकास के सफर में छूटे किनारे

'समावेशी विकास के 11 वर्ष' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अश्विनी वैष्णव ने समावेशी विकास के 11 वर्षों की यात्रा को आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए यह विश्लेषण किया है कि भारत ने अधोसंरचना, ऊर्जा, डिजिटल विस्तार तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। तथापि, इन भौतिक उपलब्धियों के बावजूद व्यापक सामाजिक-आर्थिक समावेशिता की वास्तविकता अभी भी दूर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गत 11 वर्षों की यात्रा में अवसंरचनात्मक उपलब्धियों का बड़ा संकलन प्रस्तुत किया गया है। सड़कों के 59,000 किलोमीटर नए विस्तार और 37,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण ने देश के भौगोलिक तंत्र को मजबूत किया, किंतु प्रश्न यह है कि इन सड़कों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से कितना सशक्त किया। सड़कें अवश्य पहुंचीं, मगर रोजगार, कृषि उत्पादकता और स्थानीय बाजारों में उनकी प्रभावशीलता सीमित ही रही। ऊर्जा और रसोई गैस कनेक्शन का तीव्र वितरण भी उल्लेखनीय है। सौभाग्य और उज्ज्वला योजनाओं के माध्यम से करोड़ों परिवारों को पहली बार बिजली और स्वच्छ ईंधन तक पहुंच मिली, परंतु इन सुविधाओं की लागत, आपूर्ति की स्थिरता और पुनर्भरण की चुनौतियां गरीब परिवारों के समक्ष बार-बार आर्थिक दबाव उत्पन्न करती रहीं। डिजिटल इंडिया ने तकनीकी क्रांति की नींव रखी है। 11 लाख किलोमीटर आप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित हुआ, परंतु डिजिटल खाई आज भी स्पष्ट बनी हुई है। भौतिक उपलब्धियों की चमक तभी स्थायी होगी, जब इसके केंद्र में न्यायपूर्ण, सतत और संतुलित मानव विकास हो।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

सतर्क रहे भारत

अमेरिका में राउंडवार्म की तस्करी के आरोप में एक चीनी विज्ञानी को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में इस सप्ताह यह दूसरी बार है जब किसी चीनी नागरिक के पास से संदिग्ध जैविक वस्तु मिली है। इसके पूर्व, चीनी नागरिकों के पास से फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम नामक खतरनाक फंगस बरामद हुआ था। यह घटना एक नए खतरे की ओर इशारा करती है जिसे कृषि आतंकवाद कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने के लिए शत्रुदेश इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। राउंडवार्म एक प्रकार के सूक्ष्म कीड़े होते हैं, जो इंसानों और जानवरों की आंतों या ऊतकों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार, फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम नामक खतरनाक फंगस का उपयोग किसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को गंभीर रूप से अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। इस फंगस से 'हेड ब्लाइट' नामक बीमारी होती है, जिससे गेहूं, जौ, मक्का और चावल की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यह जानवरों और इंसानों में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। चीन का भारत विरोधी रुख सर्वज्ञात है। अतः भारत को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। भारत को एयरपोर्ट पर भी निगरानी बढ़ानी होगी, ताकि कोई बैक्टीरिया, फंगस या वायरस यहां पहुंचकर कोई गंभीर समस्या उत्पन्न न कर दे।

विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

कानून का दुरुपयोग

इन दिनों देश में दहेज निरोधक कानून के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस मामले में एफआइआर दर्ज होने पर कानून भी बहुत तेजी से अपना कार्य करता है। तुरंत सभी तथाकथित आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाता। समाज में उनकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाती है। काफी साल मुकदमा चलता है। जितना दहेज मांगने का आरोप लगा था, उससे ज्यादा तो मुकदमे में खर्च हो जाता है। इन झूठे केस के कारण अनेक पति आत्महत्या तक कर चुके हैं। इस तरह के मुकदमों में गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब प्रथम दृष्टया आरोपों में सच्चाई प्रतीत हो, और यदि झूठा केस दायर किया गया हो तो लड़की को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वर्ना इस कानून के माध्यम से पति एवं उसके परिवार को सताया जाता रहेगा।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

सत्य स्पष्ट रहे, चाहे आप उस पर चल सकें या न चल सकें। प्रयास करेंगे तो उस पर दिन-ब-दिन अधिकाधिक चल सकेंगे।

- जान रस्किन

तापमान के मानक

अपने घर या कार्यालय को मनमर्जी के मुताबिक वातानुकूलित करने की प्रवृत्ति अब लोगों को बदलनी होगी। क्योंकि, आने वाले दिनों में एसी (एअर कंडीशनर) की हवा को ज्यादा ठंडा करने का विकल्प ही मौजूद नहीं होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार एअर कंडीशनर के तापमान का मानकीकरण करने वाली है। नए नियमों के तहत इसके तापमान को न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ही रखा जाएगा। इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। कई देशों में इस तरह के नियम पहले से लागू हैं। भारत में भी इसको लेकर काफी पहले से विचार किया जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू और सरकारी स्तर पर इच्छाशक्ति का अभाव इसमें रोड़ा बना हुआ था, पर अब सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए नए नियमों के मसविदे को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

देश में वातानुकूलन के लिए तापमान का मानकीकरण इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बिजली की मांग चरम पर पहुंच जाती है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान एअरकंडीशनर और हवा को ठंडा करने वाले अन्य उपकरणों का होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वातानुकूलन के समय तापमान तय सीमा में रखा जाए तो देशभर में सालाना हजारों करोड़ यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। इससे कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों पर भी दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी खासी कमी आएगी। भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी यह पहल महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे भी अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। जापान, इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एअर कंडीशनर के तापमान को लेकर पहले से ही सख्त नियम लागू हैं। जापान में तापमान की सीमा 26 डिग्री, जबकि इटली और स्पेन में 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखी गई है।

ऐसा बताया गया है कि नया नियम फिलहाल सभी नए एअर कंडीशनर पर लागू होगा। यानी आने वाले दिनों में बाजार में उपलब्ध एअर कंडीशनर में तापमान 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखा जा सकेगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि बिजली की खपत कम होने से बिल की राशि भी कम होगी। यानी समाज के मध्यम वर्ग के लिए सरकार का यह कदम राहत भरा होगा। घरों के अलावा सार्वजनिक भवनों, होटलों, माल, कार्यालयों, विपणन केंद्रों और कारों में लगे वातानुकूलन उपकरणों पर भी ये नियम लागू होंगे। हालांकि, घरों में लगे पुराने एअरकंडीशनर को लेकर सरकार की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरे पहलू से देखा जाए तो कमरे में बहुत कम तापमान रखना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रहने से सांस संबंधी समस्याएं, सर्दी-खांसी, जोड़ों में दर्द और त्वचा संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए 24-26 डिग्री का तापमान आदर्श होता है।

मनमानी पर अंकुश

दिल्ली के निजी विद्यालयों में मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ाए जाने पर सवाल उठते रहे हैं। अभी हाल ही में द्वारका में कई अभिभावकों ने सरकार की अनुमति के बिना एक विद्यालय पर शुल्क बढ़ोतरी का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि बच्चों और उनके माता-पिता पर दबाव बनाने के लिए कुछ स्कूलों में अतिरिक्त कर्मी तैनात किए जाते हैं। निजी विद्यालयों की निरंकुशता का मुद्दा अदालतों में भी उठता रहा है। ऐसा भी नहीं कि शिक्षा निदेशालय को वस्तुस्थिति मालूम न हो। सवाल यह है कि निजी विद्यालयों को मनमानी करने की छूट किसने दी? कौन लोग हैं जो इन्हें अब तक शह देते रहे हैं? लगातार शिकायतें मिलने पर दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन-2025) विधेयक पारित करने का निर्णय किया था, मगर किन्हीं कारणों से यह पेश नहीं किया जा सका था। अब इस विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने का दिल्ली मंत्रिमंडल का फैसला एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इससे शुल्क प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों की भी बड़ी राहत मिलेगी। निजी विद्यालयों को अब जवाबदेह बनना होगा। वे अभिभावकों पर मनमाने तरीके से आर्थिक बोझ नहीं डाल सकेंगे।

हैरत की बात तो यह है कि निजी विद्यालयों में शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में राशि जोड़कर कई वर्षों से वसूली की जाती रही है। विकास शुल्क के नाम पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है। मगर, अब इस पर रोक लग सकेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना शुल्क बढ़ाने पर निजी विद्यालयों और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किए थे। इसमें दोराय नहीं कि बार-बार शुल्क बढ़ाए जाने से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर नाहक ही आर्थिक बोझ पड़ता है। नया अध्यादेश लागू होने के बाद निजी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इस अध्यादेश में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनसे अभिभावकों को चिंता से मुक्ति मिलेगी। शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों को परेशान किए जाने पर पचास हजार के जुर्माने का प्रावधान निस्संदेह सरकार का सख्त कदम है।

पिछड़ता उच्च शिक्षा का स्तर

देश में विगत तीन दशकों से शैक्षिक संस्थानों के प्रति काफी नरमी बरती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मुख्य वजह भी यही है। जिस गति से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, शिक्षण संस्थाएं उससे तालमेल नहीं बैठा पाईं।

सुशील कुमार सिंह

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था उदारीकरण के बाद आगे तो बढ़ी, लेकिन उसी गति से उसमें गुणवत्ता विकसित नहीं हो पाई। उदारीकरण के तीन दशक पूरे हो चुके हैं, मगर इसका लाभ उच्च शिक्षा में केवल कमाई के अवसर के रूप में देखा गया। खास यह भी है कि तकनीकी शिक्षा के लिए आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) को मानक तय करने के लिए 1987 में बनाया गया था। इसके नियमों की खूब अवहेलना हुई। समय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भी नकेल कसने में कम ही कामयाब रहा। आकर्षक विज्ञापनों और चमचमाते सपनों के साथ युवाओं के हाथ में उच्च शिक्षण संस्थाओं ने डिग्रियां तो खूब थमाईं, पर कौशल के मामले में वे खोखले ही रह गए। यूजीसी की वेबसाइट को खंगालें, तो मौजूदा समय में सभी प्रारूपों में 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 57 केंद्रीय और 502 राज्य विश्वविद्यालय हैं। ये सभी उच्च शिक्षण संस्थान और इनसे जुड़े कालेज हर साल तकरीबन चार करोड़ से अधिक युवाओं की तकदीर बनाते हैं। ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। निराशा की बात यह है कि इनमें कई संस्थान शिक्षा को धन उगाही का जरिया बना लेते हैं और डिग्रियां बांटना एक तरह से कारोबार बन जाता है।

असल में शिक्षा कोई रातों-रात विकसित होने वाली व्यवस्था नहीं है। वैश्वीकरण के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई दरवाजे खुले। मगर व्यावहारिक तौर पर अब ये विफल दिखाई देते हैं। भारत में विगत तीन दशकों से शिक्षा संस्थानों के प्रति काफी नरमी बरती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मुख्य वजह भी यही है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। संसार की सबसे बड़ी युवा आबादी यहीं है। जिस गति से शिक्षा लेने वालों की संख्या यहां बढ़ी, शिक्षण संस्थाएं उससे तालमेल नहीं बैठा पाईं। कुछ क्षेत्रों में बिना किसी नीति के कमाने वाली शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई। इंजीनियरिंग कालेज इसी तर्ज पर विकसित हुए और यह बात तब और पुख्ता हो जाती है, जब आंकड़े बताते हैं कि देश में इंजीनियरिंग की सफलता दर आम तौर पर दस फीसद से अधिक नहीं होती है जबकि हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक कालेजों से निकलते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2024 में 40 फीसद आइआइटी स्नातक भी नौकरी पाने में असफल रहे। 'इंडियाज रोजुएट स्किल्स इंडेक्स' के अनुसार, देश में लगभग 57 फीसद स्नातकों के पास आवश्यक कौशल नहीं है।

सवाल उठता है कि शैक्षणिक वातावरण हमारे यहां कैसा है। अब शिक्षण संस्थानों को सुशासन के मार्ग की ओर ले जाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा को लेकर दो प्रश्न उभरते हैं। पहला यह कि क्या विश्व परिदृश्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच उच्चतर शिक्षा, शोध और ज्ञान के विभिन्न संस्थान स्थिति के अनुसार बदल रहे हैं? दूसरा क्या अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का कोई बड़ा लाभ मिल रहा है। यदि हां, तो सवाल यह भी है कि क्या परंपरागत मूल्यों और उद्देश्यों का संतुलन इसमें बरकरार है? विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू में ज्ञान के सृजन का हस्तांतरण भूमंडलीय हिस्सेदारी के आधार पर हुआ था। धीरे-धीरे बाजारवाद के कारण शिक्षा गुणवत्ता के मामले में पिछड़ती गई। वर्तमान में तो इसे बाजारवाद और व्यक्तिवाद के संदर्भ में परखा और जांचा जा रहा है। तमाम ऐसे कारकों के चलते उच्च शिक्षा सवालों में घिरती चली गई। देश में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक क्यों हुई, इसे समझना होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि इस क्षेत्र में उन मानकों को कहीं अधिक ढीला छोड़ दिया गया, जिसे लेकर एक निश्चित नियोजन होना चाहिए था। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तभी आती है, जब इसे शोधपरक बनाने का प्रयास किया जाता है न कि रोजगार जुटाने मात्र का जरिया बनाया जाता है। निजी विश्वविद्यालय फीस वसूलने में पूरा दम लगाए रखते हैं, पर उच्च शिक्षा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता कम ही दिखती है। कोई दो मत नहीं कि यहां शिक्षा एक व्यवसाय है, इसका अपना एक आकर्षण है। ऐसा लगता है कि अब तो आनलाइन व्यवस्था में शिक्षण संस्थान मोबाइल और लैपटाप में सिमट चुके हैं।

देश में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक क्यों हुई, इसे समझना होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि इस क्षेत्र में उन मानकों को कहीं अधिक ढीला छोड़ दिया गया, जिसे लेकर एक निश्चित नियोजन होना चाहिए था। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तभी आती है, जब इसे शोधपरक बनाने का प्रयास किया जाए, न कि रोजगार जुटाने मात्र का जरिया बनाया जाए। निजी विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता कम ही दिखाई देती है। यहां शिक्षा एक व्यवसाय है, इसका अपना एक आकर्षण है। ऐसा लगता है कि अब तो आनलाइन व्यवस्था में शिक्षण संस्थान मोबाइल और लैपटाप में सिमट चुके हैं।

तीन नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों पर सवाल उठाया था। शीर्ष अदालत ने उड़ीसा हाईकोर्ट के इस फैसले को कि पत्राचार के जरिए तकनीकी शिक्षा सही है, उसे खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। शीर्ष अदालत के इस फैसले से मेडिकल, इंजीनियरिंग और फार्मेसी समेत कई अन्य पाठ्यक्रम जो तकनीकी पाठ्यक्रम की श्रेणी में आते हैं, उन्हें लेकर विश्वविद्यालय अब मनमानी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इस फैसले से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी समर्थन मिलता है जिसमें कंप्यूटर विज्ञान में पत्राचार के माध्यम से ली गई डिग्री को नियमित तरीके से हासिल डिग्री की तरह मानने से इनकार कर दिया गया था। कचोटने वाली बात यह भी है कि उच्च शिक्षा के नाम पर चौतरफा अव्यवस्था फैली हुई है। बीते दो दशक में दूरस्थ शिक्षा को लेकर गली-मोहल्लों में दुकानें खुलने का सिलसिला आज भी जारी है।

उत्तर प्रदेश के कई नामी-गिरामी विश्वविद्यालय भी इस मोह से नहीं बच पाए। स्नातक और परास्नातक समेत कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लेकर दूरस्थ माध्यम से बिना किसी खास करीदी के न केवल केंद्र खोलने की अनुमति दी गई, बल्कि स्वयं के साथ इससे जुड़े ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाने लगे। इतना ही नहीं, बीटेक से लेकर एमबीए तक की डिग्रियां भी दूरस्थ माध्यम से ऐसे केंद्रों से सहज रूप से उपलब्ध होने लगी। दरअसल, शिक्षण संस्थाओं ने व्यवसाय अधिक किया, जबकि नैतिक धर्म का पालन करने में कोताही बरती है। हमारे छह पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आमतौर पर राष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लगातार पांचवें वर्ष 'टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' का बहिष्कार जारी रखा है। वैश्विक स्तर पर, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार नौवें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि एमआइटी स्टैनफोर्ड को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था किस मुकाम पर है? जाहिर है जब तक उच्च शिक्षण संस्थान चलाने वाले गंभीर नहीं होंगे, शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझेंगे और शोध के मामले में गंभीर नहीं होंगे, तब तक यह व्यवस्था हांफती रहेगी और इसमें सुशासन की दरकार बनी रहेगी।

आत्मचिंतन का दर्पण

मोनिका राज

मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वह जो भी देखता है, अनुभव करता है, उसका मूल्यांकन करने की चेष्टा करता है। विडंबना है कि यह मूल्यांकन अक्सर बाहरी दुनिया तक ही सीमित रहता है। जीवन में जब भी कोई घटना घटती है- सुखद या दुखद, मनुष्य की दृष्टि अपने भीतर झांकने के स्थान पर बाहर की ओर चौड़ती है। वह अपने संकटों, उलझनों और दुखों का कारण दूसरों को मानता है, जैसे जीवन की सारी विसंगतियां बाहरी तत्त्वों की देन हों और उसका अपना मन बिल्कुल निर्दोष हो।

यह प्रवृत्ति केवल सामान्य जन में ही नहीं, बल्कि सुशिक्षित और धर्म-प्रवृत्त लोगों में भी समान रूप से देखी जाती है। क्योंकि, मन की आदत यही है- दोषारोपण की। किसी भी असफलता, दुख, अपमान का कारण बाहर के व्यक्तियों, परिस्थितियों, शासन, व्यवस्था या समाज को ठहराना आसान होता है। यह आसान रास्ता आत्ममंथन की उस कठिन प्रक्रिया से बचने का एक साधन है, जिसमें व्यक्ति को अपने भीतर की लालसा और दुर्बलता से साक्षात्कार करना होता है। मनुष्य का मन एक दर्पण के समान है, पर यह दर्पण समय और परिस्थितियों के साथ टूट गया है। ईर्ष्या और अहंकार की मोटी परतों ने इसे इतना ढक दिया है कि इसमें अपना असली चेहरा दिखना बंद हो गया है। जब यह दर्पण ही मैला हो, तब उसमें दोष अपना नहीं, दूसरों का ही दिखेगा। यही कारण है कि व्यक्ति अपने भीतर झांकने के स्थान पर बाहर की दुनिया को दोषी ठहराता है।

आत्मचिंतन एक शब्द नहीं, साधना है। यह वह प्रक्रिया है, जो हमें अपने ही भीतर की परछाइयों से साक्षात्कार कराती है। यह हमें बताती है कि हमारी प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, पीड़ा और यहां तक कि हमारे निर्णय भी हमारे ही अंतःकरण की उपज हैं। जब आत्मचिंतन के दीप से भीतर का अंधकार उजाला बनता है, तब जीवन का वास्तविक आलोक सामने आता है। हमें यह समझना होगा कि दूसरों के दोष गिनाना सहज है, पर अपने दोषों को देखना कठिन, क्योंकि आत्मस्वीकृति में साहस चाहिए, अपने ही भीतर के राक्षसों से लड़ने का हौसला चाहिए। पर जब हम एक बार भीतर झांकना शुरू करते हैं, तो हमारी चेतना का एक ऐसा नया अध्याय आरंभ होता है, जो हमें बाहर के नहीं, भीतर के युद्ध का योद्धा बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है, तो यह सोचता है कि सामने वाले ने उसे अपमानित किया। अगर वह आत्मचिंतन करे, तो पाएगा कि उसका अहंकार, उसकी अपेक्षाएं, असंवेदनशीलता- ये सब मिल कर उसे उस अपमान का अनुभव कराती हैं। यह अनुभव बाहरी नहीं, भीतरी है। दुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब तक यह बोध नहीं होगा, तब तक आत्मबोध संभव नहीं। बाहर की घटनाएं तो केवल आवरण हैं, मूल तत्त्व भीतर छिपा है। मसलन, अगर कोई व्यक्ति हमें क्रोधित करता है, तो हम सोचते हैं कि उसने हमें क्रोधित किया। सच्चाई यह है कि हमारे भीतर क्रोध पहले से था, वह केवल प्रकट हुआ। अगर भीतर शांति हो, तो कोई भी व्यक्ति हमें क्रोधित नहीं कर सकता। यह सत्य तभी प्रकट होता है, जब हम बाहर नहीं, भीतर देखते हैं। संतों ने बार-बार आत्मचिंतन पर बल दिया है। संत कबीर कहते हैं- 'बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।' यानी जब व्यक्ति अपने ही अंतर्मन को खोजता है, तब उसे अपनी कमजोरियां दिखती हैं और यहीं से शुरू होती है वास्तविक उन्नति की यात्रा।

आज का समाज जितना जटिल होता जा रहा है, उतनी ही आवश्यकता आत्मचिंतन की है। हम अपने संबंधों, कार्यक्षेत्र, समाज और राजनीति में जिस प्रकार दूसरों को दोषी ठहराने का चलन बढ़ा रहे हैं, वह केवल बाह्य संघर्षों को जन्म देता है। ये संघर्ष कभी समाप्त नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति भीतर जाकर यह न देखे कि उसके विचारों और निर्णयों में कितनी विकृति है। आत्मचिंतन से जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदलती हैं। जो व्यक्ति पहले केवल दोष देखता था, वही अब कारण देखता है। यह अंतर सूक्ष्म, लेकिन प्रभावशाली है। जब व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को पहचानता है, तभी वह बाहर की शांति की कामना छोड़ कर भीतर की शांति की साधना करता है।

दुनिया मेरे आगे

आत्मचिंतन एक सतत प्रक्रिया है। यह एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में इसे अपनाना पड़ता है। यह ऐसी साधना है, जिसमें व्यक्ति किसी गुरु पर निर्भर नहीं रहता, न किसी बाहरी अनुशासन पर, वह अपने अंतःकरण को ही अपना पथप्रदर्शक बनाता है।

आत्मचिंतन एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, हर छोटे-बड़े निर्णय और संबंध में इसे अपनाना पड़ता है। यह वह साधना है, जिसमें व्यक्ति न तो किसी गुरु पर निर्भर रहता है, न किसी पंथ या बाहरी अनुशासन पर, बल्कि वह अपने अंतःकरण को ही अपना पथप्रदर्शक बनाता है। आत्मचिंतन का दर्पण ही वह साधन है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि बाहर की दुनिया केवल प्रतिबिंब है- मूल स्वरूप हम खुद हैं। जब यह बोध होता है, तब जीवन की दिशा बदलती है और व्यक्ति केवल घटनाओं का शिकार नहीं रहता, बल्कि जीवन का सर्जक बन जाता है।

टूट गई दोस्ती

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती दुनिया भर में चर्चा में रही है। एक तरफ दुनिया का सबसे प्रभावशाली राजनेता और दूसरी तरफ सबसे अमीर उद्योगपति। अब इन दोनों के बीच मतभेद उभर आए हैं, जो जुबानी जंग का रूप ले चुके हैं। हाल ही में ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों टेस्ला और 'स्पेसएक्स' के साथ सरकारी अनुबंधों में कटौती की घोषणा की है। इसके जवाब में मस्क ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि वे ड्रैगन कैप्सूल की सेवा बंद कर सकते हैं। यह कैप्सूल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक यात्रियों व अन्य सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है, जब अमेरिका की बोइंग कंपनी का 'स्टारलाइनर' यान विफल हो गया। इसके बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को मस्क के ड्रैगन कैप्सूल से सुरक्षित पृथ्वी पर लाया गया। दूसरी ओर मस्क का मानना है कि ट्रंप की नीतियां उनकी योजना के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रही हैं।

- वलप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

समाज भी गुनहगार

संपादकीय 'दरकते रिश्ते' (दस जून) पढ़ा। राजा रघुवंशी की मौत का प्रत्यक्ष गुनहगार कौन है? यह साफ दिखता है। उनकी पत्नी सोनम से पूछताछ के बाद पूरी तस्वीर सामने आ रही है। सवाल उठता है कि क्या रघुवंशी की मौत का असली गुनहगार हमारा समाज नहीं है, जो शादी से पूर्व लड़कियों की रजामंदी नहीं पूछता। या यह कहें कि घर की बेटियों और बहनों को खुल कर बात नहीं की जाती है। यह हमारी रूढ़ियादी मानसिकता है। विवाह पूर्व संबंध को अक्सर छिपा लिया जाता है। दुखद यह कि विवाह के बाद भी ऐसे रिश्ते चलते रहते हैं। विवाह पवित्र बंधन जरूर है, हमारी संस्कृति में, पर क्या सामाजिक संस्कृति अब वैसी बची है। अगर नहीं, तो बदलती मान्यताओं के अनुरूप कानूनी और सामाजिक सुधार की जरूरत मालसूस की जानी चाहिए।

- मुकेश कुमार मनन, पटना

चुनौतियां कम नहीं

केंद्र में राजग सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा और सहयोगी दलों में नया जोश दिखाई देता है। सत्तारूढ़ दल के सभी घटकों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और कार्यशैली की सराहना की है। हालांकि, विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कई खामियां गिनाई हैं। मगर, भाजपा नीत केंद्र सरकार ने कुछ उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत से लोगों को काफी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने कई ढांचागत निर्माण कराए, जिनमें नए संसद भवन का निर्माण भी है। इस दौरान देश ने महामारी का सामना किया, पर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। मगर, सरकार के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना होगा। सिर्फ पिछली उपलब्धियों का गुणगान मात्र से देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हिंसा के जोखिम

इंटरनेट पर हिंसक सामग्री उपलब्ध है। इसे मोबाइल और लैपटाप पर किशोर व युवा हर समय सहजता से देख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। इस तरह की सामग्री आसानी से नहीं मिलती थी। मगर अब इलेक्ट्रानिक मीडिया पर भी हिंसक खबरें इतनी बार दिखाई जाती हैं कि उसका खासकर बच्चों, किशोर और युवाओं पर बुरा असर पड़ता है। लिहाजा इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना होगा। इंटरनेट और अन्य मंचों पर हिंसक सामग्री डालने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी सामग्री बच्चे न देखें, इसके लिए कुछ गंभीर उपाय करने होंगे। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को मोबाइल खरीद कर न दें। कई परिवारों में यह पहल हुई, जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

- मनमोहन राजावत 'राज', शाजापुर

मोदी सरकार
महत्वपूर्ण 11 साल

मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में साहसी सुधारों से शासन का विमर्श बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस पद पर 11 साल बीतने का अवसर भारत की राजनीतिक एवं विकास यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय है। पिछले दशक में मोदी सरकार ने व्यापक बदलाव किए हैं जिनमें आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक बदलाव शामिल हैं। इससे शासन-प्रशासन का नया युग शुरू हुआ है जो प्रदर्शन, जवाबदेही और राष्ट्रीय गौरव पर आधारित है। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर जोर दिया है जिनमें मोदी सरकार की सामाजिक-आर्थिक से लेकर राजनीतिक उपलब्धियां शामिल हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक रूप से दसवीं अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को लक्षित किया गया जिनमें जन धन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और आवासीय पहलें शामिल हैं। इनसे लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले जिसे सरकार विकास का 'गरीब कल्याण' माडल बताती है। मातृत्व अवकाश के विस्तार, 'लक्ष्मी दीदी' जैसे स्वयंसेवा समूहों के उभार तथा महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में तेज प्रगति के लक्षण महिला-नीत विकास में दिखाई दिए हैं। इन क्षेत्रों में जमीनी उद्यमिता से लेकर अंतरिक्ष खोज तक शामिल हैं। सरकार का दावा है कि उसने भारतीय राजनीति की पहचान आधारित तुष्टिकरण से बदल कर परिमाणोन्मुख माडल में बदल दिया है जहां लफ्फाजी के बजाय 'रिपोर्ट कार्ड' सार्वजनिक नेतृत्व को परिभाषित करते हैं। मोदी के कार्यकाल का एक सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समय कोविड-19 वैश्विक महामारी थी जिसके दौरान भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया तथा 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। इसके साथ ही 'वैक्सीन मैत्री' तथा 'आपरेशन गंगा' जैसी त्वरित आपात कार्रवाइयों के माध्यम से भारत विश्व स्तर पर जिम्मेदार देश के रूप में उभरा। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने की घोषणा भारत के आंतरिक एकीकरण प्रयासों में मील का पत्थर है। इस कदम के बाद स्थानीय चुनावों में मतदाताओं की रिकार्ड सहभागिता सामने आई जिसे क्षेत्र का गहरा लोकतांत्रिक सामान्यीकरण बताया जा रहा है।

मोदी सरकार में तेज ढांचागत विकास भी एक प्रमुख आयाम है। काफी समय से लंबित चिनाब पुल का निर्माण अंततः पूरा हुआ और इस साल उसका उद्घाटन किया गया। पिछले वर्षों के अन्य उल्लेखनीय सुधारों में तीन तलाक समाप्त करना, नागरिकता संशोधन कानून तथा वक्फ कानूनों में संशोधन हैं। सरकार के अनुसार इन सबका उद्देश्य लंबे समय से व्याप्त सामाजिक असंतुलन को ठीक करना है। मोदी सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है कि वह वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाएगी जो देश की स्वतंत्रता की शताब्दी होगी। सरकार इस उद्देश्य से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धान्त से निर्देशित है। हालांकि, मोदी के आलोचक लोकतांत्रिक पिछले वर्षों में स्वतंत्रताओं की कमी तथा सत्ता के केन्द्रीकरण की ओर इशारा करते हैं, पर विरोधी भी यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने व्यापक परिवर्तन आए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 11 सालों ने न केवल भारत में शासन-प्रशासन को पुनः परिभाषित किया है, बल्कि नागरिकों की उनके नेताओं से उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। चाहे इसे परिवर्तन की राजनीति के रूप में देखा जाए अथवा विपक्षी इसे ध्रुवीकरण कहें, पर इस युग में असंदिग्ध रूप से देश की राजनीतिक और विकास सोच में अंतर आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग तीस साल बाद केन्द्र में पहली संपूर्ण बहुमत वाली गैर-कांग्रेस सरकार बनाई थी। इस सरकार ने पिछले 11 साल में कांग्रेस तथा कांग्रेस समर्थित अन्य खिचड़ी सरकारों की तुलना में अभूतपूर्व और असाधारण परिवर्तन किए। तकनीक का प्रयोग कर सरकार ने अनेक योजनाओं में सब्सिडी सीधे लाभार्थी समूहों के खाते में भेजी जिससे जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर लगाम लगी। मोदी सरकार ने देश की जनता व खासकर नौजवानों में भविष्य के प्रति आशा और विश्वास पैदा किया है।

व्यापक मुफ्त खाद्यान्न योजना

भारत सरकार लगातार 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कर रही है। इस योजना की समीक्षा कर तत्काल सुधार की आवश्यकता है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

पिछले साल अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय शोध परिषद-आईसीआरआईईआर ने 'भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तार्किकीकरण' शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना'-पीएमजीकेवाई से लगभग 20 मिलियन टन अनाज चोरी हो जाता है जिससे हर साल केन्द्र सरकार को लगभग 70,000 करोड़ रुपये का घाटा होता है। पीएमजीकेवाई के अंतर्गत केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई और अन्य राज्य एजेंसियों को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदने तथा लगभग 820 मिलियन लोगों को उसके मुफ्त वितरण की व्यवस्था करने को कहती है। यह कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस के अंतर्गत सस्ते गल्ले की दुकानों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इसके पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति एफसीआई व अन्य राज्य एजेंसियों को सब्सिडी के रूप में की जाती है जिसमें किसानों को भुगतान किए एमएसपी के साथ ही हैंडलिंग एवं वितरण पर आने वाला खर्च-एचडीसी आता है।

हालांकि, पीएमजीकेवाई 1 जनवरी, 2023 से लागू है, पर उसके पहले भी केन्द्र 820 मिलियन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून या एनएफएसए के अंतर्गत गेंहू, चावल व मोटे अनाज अत्यधिक सस्ते 2, 3 व 1 रुपये किलो के दाम पर देती थी। इसके साथ ही अप्रैल, 2020 से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज 820 मिलियन लाभार्थियों को पीएमजीकेवाई के अंतर्गत 'मुफ्त' दिया जाता है ताकि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव से उबर सकें।

1 जनवरी, 2023 से उनको पीएमजीकेवाई के अंतर्गत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पीडीएस से चोरी के बारे में अनेक जमीनी रिपोर्टें सामने आई हैं। नवीनतम खुलासा उत्तर प्रदेश के बरेली, आगरा और मेरठ डिवीजनों से सामने आया है जहां 2015 से 2018 के बीच एनएफएसए के अंतर्गत 2, 3 व 1 रुपये किलो पर दिया जाने वाला गेंहू, चावल व मोटा अनाज 'अयोग्य व्यक्तियों' को दिया जा रहा था जिससे असली लाभार्थी इससे वंचित रह जाते थे। पिछले साल पश्चिम बंगाल से भारी घोटाले की खबरें आई थीं जहां पीडीएस से वितरण के लिए आए चावल को निजी स्वामित्व वाली चावल मिलों को पहुंचा दिया जाता था जो इसे पालिश करने के बाद खुले बाजार में भारी मुनाफा लेकर बेच देते थे। इस व्यापक चोरी का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय-ईडी इस मामले की जांच कर रही है और उसके अनुमान से यह घोटाला लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये का है।

यह चोरी लगभग एक दशक से जारी थी। 2016 में पंजाब के अनाज गोदामों से भारी मात्रा में अनाज गायब होने की खबरें आई थीं जिससे राज्य में अनाज खरीद कार्यक्रम में शामिल बैंकों से भारी घोटाले की आशंका पैदा हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई के निर्देश पर बैंकों को ऐसे नुकसान से बचने के प्रयास किए गए थे जो लगभग 12,000 करोड़ रुपये का था। इसके कारण केन्द्र सरकार ने इस नुकसान की भरपाई 'खाद्य सब्सिडी' बजट से करने से इनकार कर दिया था। चोरी के ऐसे असंख्य मामले थे जो जनता की नजर से छिपे रहे। कुल मिला कर इन घोटालों से सरकार के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। इसलिए जब केन्द्र के खाद्य सब्सिडी बिल का विस्तार 2024-25 तक करने का निर्णय हुआ तो इसके बड़े हिस्से की चोरी का संदेह भी पैदा हुआ। इसका मुख्य कारण खाद्य सब्सिडी लागू करने का तरीका था।

इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी से कीमत शून्य करने का निर्णय हुआ, जबकि 2013 से दिसंबर, 2022 तक मूल्य को बहुत कम 2, 3 व 1 रुपये किलो पर रखा जाता था। इसकी तुलना सप्लाई पर आने वाले खर्च से की जानी चाहिए जो वर्तमान समय में गेंहूं के लिए प्रति किलो 27 रुपये तथा चावल के लिए प्रति किलो 39 रुपये है। इस प्रकार सप्लाई श्रृंखला में लगभग 55 मिलियन टन अनाज को पीडीएस से वितरण के लिए रखने का अर्थ और इसकी कीमत शून्य करने का अर्थ सैद्धिक लोगों को अवैध तरीके से मुनाफा कमाने के लिए चोरी के खुले आमंत्रण की तरह है।

मूल रूप से सस्ता अनाज भारत के गरीबों के लिए है। भारत की जनसंख्या में गरीबों की संख्या 15-20 प्रतिशत से अधिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान समय में लाभार्थियों की संख्या जनसंख्या का 59 प्रतिशत है। शांता कुमार कमेटी, 2015 के अनुसार पीडीएस से लाभार्थियों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि 2015 से लगभग 250 मिलिय लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। इसे देखते हुए लाभार्थियों की संख्या में समुचित कमी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां लाखों 'अवैध' लोग इससे बाहर जाने से इनकार कर रहे हैं, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह लाभार्थियों की सूची को 2021 की जनगणना के अनुसार अद्यतन करे क्योंकि वर्तमान सूची 2011 की जनगणना के आधार पर है। इस आधार पर अतिरिक्त 100 मिलियन लोगों को मुफ्त राशन देना होगा।

यदि सूची से कोई नाम न हटाए जाएं तो इस योजना का विस्तार 920 मिलियन लोगों तक हो जाएगा। 2013 में लागू एनएफएसए कानून के अनुसार लाभार्थियों को गेंहूं, चावल व मोटे अनाजों के लिए 2, 3 व 1 रुपये किलो का भुगतान करना होता था। इसने दरों को तीन साल के लिए तय कर दिया था। इस प्रकार 2016 से दाम बढ़ाने पर कोई विधिक बाधा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद दाम बढ़ाना तो दूर, मोदी सरकार ने कीमतें घटा कर शून्य कर दीं। इस प्रकार भ्रष्ट राजनेताओं-अधिकारियों और स्थानीय राशन व्यापारियों-मिलों के बीच शून्य मूल्य वाली पीडीएस सप्लाई व उच्च बाजार मूल्यों के बीच 'भारी अंतर' को हड़पने का प्रयास जारी रहता है। वे मोदी सरकार द्वारा लागू सर्वोत्तम तकनीकी हस्तक्षेपों को भी धता बता देते हैं। इनमें राशन दूकानों पर पीओएस मशीनें लगाना, खरीद से लेकर वितरण तक सप्लाई श्रृंखला का डिजिटलीकरण, आधार कार्ड के आधार पर लाभार्थियों की वैधता, आदि शामिल हैं। खरीद के मोर्चे पर भी ऐसे तथ्य सामने आए हैं जहां छोटे और गरीब किसान अपना उत्पाद राज्य एजेंसियों को नहीं बेच पाते हैं, जबकि उनको पोर्टलों पर पंजीकरण कराना होता है। इससे वे एमएसपी तथा खरीद की गारंटी से वंचित रह जाते हैं, जबकि अधिकारियों की मिलीभगत से संदिग्ध व्यापारी इसका लाभ उठाते हैं।

चोरी को वास्तव में तभी रोका जा सकता है जब सरकार डीबीटी तरीके से सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे। उदाहरण के लिए, गेंहूं की सप्लाई पर प्रति किलो आने वाले 27 रुपये खर्च को देखते हुए वह लाभार्थी के खाते में योजना के अंतर्गत पांच किलो राशन के लिए प्रति माह 135 रुपये भेज सकती है। इस पैसे से उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार बाजार से खरीद कर सकते हैं, जिसके लिए वे वर्तमान समय में पीडीएस पर निर्भर रहते हैं। इससे पीडीएस दूकानदार सामान्य खुदरा विक्रेताओं की तरह काम कर सकेंगे। इस व्यवस्था में राज्य एजेंसियों को लाभार्थियों में वितरण के लिए अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। इसी प्रकार किसान भी अपने उत्पाद उसी प्रकार बाजार में बेच सकेंगे जिस प्रकार कोई अन्य वस्तु बाजार-संचालित ढांचे में बेची जाती है। इसके लिए तीन केन्द्रीय कृषि कानूनों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए जो किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ज्यादा विकल्प देंगे तथा उनको इनकी अच्छी कीमत मिलेगी।

इस प्रकार व्यवस्था में मुफ्त मिलने वाला अनाज न होने पर उसकी चोरी की संभावना भी समाप्त होगी। इसके साथ ही फर्जी लाभार्थियों के नाम पर राशन हड़पने का खेल बंद हो जाएगा। इससे सरकार अवांछित लोगों को सूची से हटा कर सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकेगी। इससे किसानों से खरीद की 'गारंटी' से मुक्ति मिलेगी तथा सब्सिडी की वर्तमान विसंगतियों से मुक्ति मिलेगी। संक्षेप में कहा जाए तो रकार योजना के पुनर्गठन से इसके दुरुपयोग व चोरी को रोक सकेगी तथा प्रतियोगिता व क्षमता आधारित बाजारों का विकास होगा और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।

सड़कें जिन्होंने भारत के विकास की दिशा बदल दी!

नितिन गडकरी
(लेखक, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं)

जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, उसी क्षण से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चुनियादी ढांचे के विकास को हर चीज से ऊपर रखा। इस दिशा में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय चुनियादी ढांचे के विकास का केंद्र बिंदु बन गया। मोदी के नेतृत्व में, इस मंत्रालय ने न केवल देश के आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि 2014 से इन 11 वर्षों में इसे एक नया आयाम भी दिया है।

राजमार्गों के निर्माण - पूर्ण और आगामी दोनों - ने देश के विकास की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुशल राजमार्ग, जलमार्ग और रेलवे रसद लागत को कम कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना देखते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें निर्यात बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि होगी। पिछले 11 वर्षों में बनाई गई सड़कों ने हमारी रसद लागत को 16 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है और अगले साल हम इसे और घटाकर 9 फीसदी करने का लक्ष्य रखते हैं। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, हम अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और भारत को विश्वगुरु बनने की दिशा में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर में 25 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहा है। बंदरगाहों को जोड़ने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग भी बनाए जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास भी आकार ले रहे हैं। 22,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई बौद्ध सर्किट परियोजना ने दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, सिंगापुर और जापान से भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

इसके साथ ही, चार धाम स्थलों - बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री - पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तीन गुनी हो गई है। केदारनाथ को जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ रुपये की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाली सड़क का लगभग 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। भारत में, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में, 'उड़ने वाली बसों' का सपना सच होने की कगार पर है। इसमें हवाई बसें, फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसें और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए डबल-डेकर उड़ने वाली बसें शामिल हैं। दिल्ली के धौला कुआं से मानेसर तक स्काईवे सिस्टम पर आधारित हवाई बस सेवा लगभग अपने अंतिम चरण में है। मुझे विश्वास है कि यह प्रयोग इस विशेष मार्ग पर लगातार यातायात की भीड़ को हल करने में महत्वपूर्ण होगा।

नागपुर में जल्द ही पहली फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस शुरू होगी। इसमें 135 सीटें, एक्जीक्यूटिव क्लास, सामने टीवी स्क्रीन और एयर होस्टेस जैसी बस होस्ट होंगी। इस बस की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले हर 40 किलोमीटर पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए पूरी तरह चार्ज होने के लिए रुकेगी। ऐसा काम सिर्फ दफ्तर में बैठकर डीपीआर तैयार करने से नहीं हो सकता - इसके लिए पूरे दिल से प्रयास की जरूरत होती है!

सड़क निर्माण पर आईआईएम-बैंगलोर द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) निर्माण पर खर्च किए गए हर 1 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.21 की वृद्धि हुई है, जो 3.2 गुना का गुणक प्रभाव है। नतीजतन, घरेलू उत्पादन में 9 प्रतिशत और कार की बिक्री में 10.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए काम ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है, बल्कि कई रोज़गार के अवसर भी पैदा किए हैं। यहां कुछ ध्यान देने योग्य आंकड़े दिए गए हैं: 2014 में, भारत में केवल 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे। 2024 तक, यह नेटवर्क लगभग 60 फीसदी बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है। सड़क निर्माण की दैनिक गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 28-30 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। महत्वाकांक्षी 5.35 लाख करोड़ की भारतमाला परियोजना के तहत, आर्थिक गलियारों, अंतरराष्ट्रीय सीमा सड़कों और सीमा क्षेत्र कनेक्टिविटी सहित 65,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य है। यह योजना भारत की रसद लागत को और कम करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

'गति शक्ति' और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पहल सड़क, रेलवे, वायु, जलमार्ग और बंदरगाहों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करती है, जिससे समय पर परियोजना पूरी करने में मदद मिली है। हमारे मंत्रालय ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से सड़क विकास परियोजनाओं को लागू करना भी शुरू कर दिया है, जिसने महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित किया है। इस मॉडल के तहत, 12 लाख करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

2014 में शुरू हुई यह यात्रा केवल सड़कों के बारे में नहीं है, एक तरह से, यह भारत की प्रगति की जीवन रेखा बन गई है। राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार ने न केवल यात्रा को आसान बनाया है बल्कि घरेलू व्यापार, उद्योग, पर्यटन और सुरक्षा को भी बढ़ाया है।

हमारी सरकार पहले दिन से ही समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक समावेशी विकास पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हम इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए आने वाले वर्षों में इस काम को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अब हमारे पास विश्व स्तरीय चुनियादी ढांचे के निर्माण और 2047 तक अपने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बेहतर बनाने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, ताकि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन सके। अमेरिका के पास अच्छी सड़कें इसलिए नहीं हैं क्योंकि वह अमीर है; अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पास अच्छी सड़कें हैं। दिल्ली में परिवहन भवन में मेरे कार्यालय और इससे पहले महाराष्ट्र में जब मैं मंत्री था, तब प्रदर्शित पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का यह कथन संयोग से नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से यह हमारा मार्गदर्शक मंत्र रहा है।

हम भविष्य में इस काम को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आने वाले वर्षों में भारत का सड़क बुनियादी ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बेहतर होगा - यह कोई सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन रहा है। गुणवत्ता, गति, पारदर्शिता और पर्यावरण अनुकूल नीतियों का संतुलन बनाए रखकर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी।

आप की बात

बिहार में चुनाव

बिहार का विधानसभा चुनावी दंगल इस वर्ष के अंत में होगा जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय एवं चौकोणीय या बहुकोणीय होने वाला है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पूरा फोकस बिहार चुनाव पर लगा दिया है और उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। एक समय बिहार में बहुजन समाज पार्टी-बसपा के हैं। इस बार भी बसपा ने बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी-लोजपा एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ेगी अथवा ज्यादा संख्या में अपने उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान अपनी ताकत आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जदयू बार-बार दुहरा रही है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। इससे बिहार में चुनाव और दिलचस्प हो गया है।

ट्रंप की कुटिलता

अमेरिका संभवतः भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के कुटिल प्रयास शुरू कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में बेहतरी की जो उम्मीदें बनी थीं वे अब कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। ट्रंप के हालिया रवैये से स्पष्ट है कि वह पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई पर ट्रंप की असहज प्रतिक्रिया ने यह जता दिया कि वे भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसके बजाय वे व्यापार के बहाने इस संकट को रोकने का श्रेय लेना चाहते हैं और पाकिस्तान की प्रशंसा करने से भी नहीं चूकते। ट्रंप का एक और कदम भारत के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में शेख हमजा यूसुफ और इस्माइल रोयर जैसे विवादास्पद मुस्लिम नेताओं को शामिल किया जो कट्टरपंथी माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप का बिजनेस परिवार पाकिस्तान की दयनीय हालत को देखते हुए उससे लाभ उठाना चाहता है। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने एक क्रिप्टोवाइन कंपनी में निवेश किया है जिसमें ट्रंप परिवार की काफी हिस्सेदारी है। ट्रंप भारत पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं।

– सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाकिस्तानी जासूस

पहलगाम हत्याकांड ने एक बार फिर उजागर कर दिया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को केवल बाहरी नहीं, बल्कि देश में पाकिस्तानी जासूसों से भी गहरा खतरा है। जासूसों की हालिया पकड़धकड़ से स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विभिन्न हथकंडों का उपयोग कर रही है। वह लोगों को धन का लालच देती है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर या लालची लोगों को जासूसी के लिए तैयार किया जाता है। वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे जसबीर सिंह और ज्योति मल्होत्रा के फॉलोअर्स उन्हें भारत-विरोधी प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है। आईएसआई का बेहद खतरनाक तरीका हनी ट्रैप है जिसके माध्यम से वास्तविक या आभासी पाकिस्तानी लड़कियों के माध्यम से लोगों को अपने चंगुल में लिया जाता है। इसके साथ ही कट्टरपंथ और जिहाद का इस्तेमाल कर भारतीय मुस्लिम नौजवानों को बहकाया जाता है। थानों में लापता पाकिस्तानी नागरिक रजिस्टर की मौजूदगी से स्पष्ट है कि पाकिस्तानी नागरिक पर्यटक या व्यवसायी बनकर भारत आते हैं, लेकिन फिर भूमिगत हो जाते हैं। यह गंभीर खतरे का संकेत है।

अमेरिका में अराजकता

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उम्मीद से विपरीत जा रहा है। राष्ट्रपति के विवादित फैसले अमेरिका में अराजकता पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में इस समय गहरा आंतरिक संकट है जिसका केंद्र बिंदु है ट्रंप की सख्त अप्रवासी नीति। लॉस एंजेलिस में शुरू हुए दंगे अब न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में फैल चुके हैं जिससे देश गृहयुद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ता दिख रहा है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनकी अमेरिका को महान बनाने की नीति विवादों में रही है लेकिन मौजूदा स्थिति उनकी अब तक की सबसे बड़ी नाकामी के रूप में देखी जा रही है। नेशनल गार्ड की भारी तैनाती और पुलिस की फायरिंग के बावजूद लॉस एंजेलिस के हाईवे, पैसामाउंट और कॉम्पटन जैसे इलाकों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मेक्सिकन अप्रवासी अमेरिका की कुल विदेशी आबादी का 23 प्रतिशत हैं। वे ट्रंप की डिपोर्टेशन नीति से बेहद आक्रोशित हैं। अप्रवासियों की गिरफ्तारी और उन पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की धमकी ने जनता में भय और आक्रोश को जन्म दिया है। यह संकट ट्रंप की साख की परीक्षा है जिसमें वे विफल रहे हैं।

– अमृतलाल मारू, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com

चिंतन

रक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश व टेक तैयारी की जरूरत

भारत को चीन व पाकिस्तान से रक्षा चुनौतियां हैं। अब बांग्लादेश भी सिरदर्द बन रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और उग्रवाद भी भारत के लिए चुनौतियां हैं। ज्यों-ज्यों भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक ताकत के तौर पर उभरेगा, सामरिक चुनौती बढ़ती जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि आज का भारत सैन्य रूप से काफी मजबूत है और भारतीय रक्षा क्षेत्र सभी प्रकार के सैन्य उपकरणों व हथियारों से लेस है, लेकिन जिस तेजी से वार तकनीक बदल रही है और इसमें लेजर, ड्रोन व साइबर तंत्र की एंट्री हो रही है, समूचे डिफेंस सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत महसूस हो रही है। आज विश्व में दो सैन्य संघर्ष को देखें, तो जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें केवल दो देश ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि युद्ध मित्र राष्ट्रों के बीच होने लगता है। रूस व यूक्रेन जंग ने दिखाया है कि दोनों पक्षों को बाहरी मदद मिल रही है। भारत व पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ऐसा देखने को मिला। चीन व तुर्किये खुलकर पाकिस्तान के साथ आए व अमेरिका पाक की तरफ झुका दिखा। इसलिए भारत को मजबूत रक्षा तैयारी की जरूरत है, वह भी स्वदेशी दम पर। यूक्रेन ने रूस में जिस प्रकार से अंदर घुस कर ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया, उससे भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को उस स्तर से भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। सरकार ने वर्ष 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उस वक्त तक भारत का रक्षा निर्यात पचास हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारतीय स्वदेशी सैन्य अस्त्र-शस्त्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि आयातित महंगे उपकरणों ने अपनी सीमाएं दिखाईं। यहां से भारत के लिए अपने रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ इसे उच्च तकनीक आधारित विकसित करना चाहिए। आतंकवाद से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा क्षेत्र को 'आत्मनिर्भर भारत' के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में तैयार करना होगा। वर्ष 2014 में वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग 40,000 करोड़ रुपये था, जो आज 1.30 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये का था। भारत में निर्मित रक्षा उत्पाद लगभग 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। इस स्थिति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। रक्षा बजट को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ रुपये किया गया था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह 6.81 लाख करोड़ रुपये है। यह पिछले वित्त वर्ष से 9.5 फीसदी अधिक है। अगले बजट में इसमें 50 हजार करोड़ की वृद्धि हो सकती है। इसे करीब 8 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर ले जाना होगा। पिछले कुछ सालों में भारत में रक्षा खर्च में करीब 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और भारत दुनिया में सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में भी है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। भारत को नई रक्षा तैयारियों में काउंटर ड्रोन सिस्टम, लेजर ड्रोन किलिंग सिस्टम, हार्ड किल ड्रोन सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए और ड्रोन झुंडों को मारने के लिए मोबाइल 'माइक्रो मिसाइल' सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। भारतीय नेवी अभी 'माइक्रो मिसाइल' सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) गाइडेड ड्रोन ने अब कम खर्चे में प्रभावी वार टूल के रूप में अपनी क्षमता साबित की है। भारत को इस क्षेत्र में अधिक निवेश करना चाहिए।

गरीबी उन्मूलन
रवि शंकर

असमानता की खाई को पाटना जरूरी

> विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित करते हुए इसे 2.15 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर तीन डॉलर प्रतिदिन कर दिया है। इस नए मानक के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। फिर भी असमानता, बेरोज़गारी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी जैसी लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में भारत के विकास की गाथा तभी लिखी जा सकती है, जब हम इस असमानता की खाई को पाटकर गरीबी को कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह तभी संभव है जब सरकार की कल्याणकारी नीतियां न केवल उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालें, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाएं।

भारत में विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है। अब हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में काफी ज्यादा कमी देखी गई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 में 27.1 प्रतिशत की अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घटकर मात्र 5.3 प्रतिशत रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन के बाद देश को अच्छी खबर मिली है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित करते हुए इसे 2.15 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर तीन डॉलर प्रतिदिन कर दिया है। इस नए मानक के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों के बारे में बताती है।

विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंत और वार्षिक बैठकों के लिए साल में दो बार जारी होने वाली ये जानकारी किसी देश की गरीबी और असमानता के बारे में तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.8 प्रतिशत हुई। शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत हुई। वहीं, ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर 7.7 प्रतिशत अंक से घटकर 1.7 प्रतिशत अंक रह गया। इसके अलावा, भारत ने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को कम करने में भी शानदार प्रगति की है। आंकड़ों के अनुसार, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2005-06 में 53.8 फीसदी से घटकर 2019-21 तक 16.4 फीसदी हो गया और 2022-23 में और अधिक घटकर 15.5 फीसदी हो गया। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की बदली हुई जिंदगी की कहानी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहां 2011 में सबसे ज्यादा गरीब आबादी थी। उन्होंने इस बदलाव में बड़ा योगदान दिया। अकेले इन्हीं राज्यों ने देशभर में गरीबी घटाने में दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा निभाया है। इस उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि यह मानव कल्याण में बड़ी प्रगति की तरफ इशारा करता है। यह आर्थिक वृद्धि और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को परिलक्षित करता है।

हमारे देश में गरीबी के कई कारण रहे हैं। देश में ग्रामीण गरीबी का मूल कारण कृषि में अर्द्ध सामंती उत्पादन संबंधों का होना है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के लिए जो कदम उठाए गए, वे नाकाफी हैं और भूमि पर बड़े किसानों का अधिकार होने से भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग सभी खेतिहर मजदूरों के परिवार, काफी संख्या में छोटे व सीमांत किसान तथा भूमिहीन गैर-कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक परिवार गरीब हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, किन्तु भूमि उतनी ही रहती है।

इससे श्रम उत्पादकता और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कम होती जाती है। कृषि में तकनीकी परिवर्तनों और खाद्यों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि का लाभ बड़े किसानों को ही हुआ है। वहीं देश में बढ़ते पूंजीवाद के

कारण नवउदारवादी नीतियों तथा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियां गरीबों के लिए अहितकर सिद्ध हुई है। बहरहाल,भारत ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि नीति, प्रयास और जनसहभागिता से गरीबी जैसी चुनौती को मात दी जा सकती है। हालांकि, इस रिपोर्ट से इतर भी हाल की कई रिपोर्टों में अत्यधिक गरीबी घटने की बात रेखांकित की गई थी। इसका कारण आर्थिक विकास दर का निरंतर मजबूत बने रहना और सरकारी नीतियां हैं।

रिपोर्ट में जहां मोदी सरकार इस बड़ी उपलब्धि की तारीफ की गई है, तो वहीं दूसरी ओर इकोनॉमी को लेकर कहा गया है कि भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024-25 तक कोरोना महामारी पूर्व प्रवृत्ति स्तर से लगभग 5 फीसदी कम थी। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत सरकार नागरिकों की वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रभावी रही है। निश्चित रूप से इस उपलब्धि में विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों मसलन आर्थिक विकास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। निस्संदेह, इसने सबसे गरीब तबके के लोगों की आय बढ़ाने में मदद की है। जाहिर तौर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिजली, शौचालयों और आवास तक इस तबके की पहुंच बढ़ाने जैसी पहल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में योगदान दिया है, जिसका नतीजा सामने है। इसके बावजूद जहां हम गरीबी उन्मूलन में मिली सफलता पर आत्ममुग्ध हैं तो वहीं समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। पिछले साल जारी की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि भारत में शीर्ष एक प्रतिशत लोगों की संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। वे लोग देश की चालीस फीसदी संपत्ति नियंत्रित करते हैं। ये असमानताएं हैं जिन्हें अवश्य ही दूर किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि एक दशक के दौरान रोजगार में भी वृद्धि हुई और ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस दौरान भारत में बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी सफलता मिली है। संघीय सरकार वाले इतने बड़े, विविधतापूर्ण देश में नीति निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए,पीएम मोदी ने कई मौकों पर कठोर परिस्थितियों और गैर-समर्थक विपक्ष के बावजूद समय पर निर्णय और नीतियों को लागू करके 1.4 बिलियन लोगों के विकास के लिए अपने समर्पण का उत्तरदायित्व निभाया है। अपने पहले कार्यकाल में उन्हें विरासत में मिली सुस्त अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक विकास के स्रोत में बदल दिया है। फिर भी असमानता, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी जैसी लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं।

ऐसे में भारत के विकास की गाथा तभी लिखी जा सकती है, जब हम इस असमानता की खाई को पाटकर गरीबी को कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह तभी संभव है जब सरकार की कल्याणकारी नीतियां न केवल उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालें, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाएं। आर्थिक कल्याणकारी नीतियों का मकसद मुफ्त की रेवड़ियां बांटना न होकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। खैर, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी पहलों, तेज आर्थिक सुधारों और जरूरी सेवाओं तक सबकी पहुंच का ही यह नतीजा है कि गरीबी दिन-ब-दिन तेजी से घट रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

अभिव्यक्ति
डॉ. मोनिका शर्मा

प्रतिनिधिमंडल में दिखा भारतीयता का मुखर भाव

बीते कई दशक से भारत आतंकवाद से जूझ रहा है। बावजूद इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर भ्रम फैलाने में पीछे नहीं रहता। बीते दिनों पहलगाम हमले के बाद की गई सफल सैन्य कार्रवाई से साथ ही हमारे देश द्वारा दुनिया के कई देशों में अपना पक्ष रखने का प्रयास भी अहम रहा। ध्यातव्य है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 'ग्लोबल-आउटरीच' के लिए सांसदों के सात प्रतिनिधिमंडलों ने दुनिया के अलग-अलग देशों का दौरा कर ना केवल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया बल्कि आतंकवाद को लेकर भारत का रुख भी स्पष्टता से रखा है। 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर अलग-अलग राजनीतिक दलों के 51 सांसदों के साथ ही राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाहों ने परायी धरती पर भारत का पक्ष रखा। सुखद है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखते हुए दुनिया के अनेक देशों का दौरा कर लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों में हर मतभेद से परे भारतीयता का मुखर भाव दिखा।

असल में आतंक के दंश के खिलाफ दिखी यह साझी अभिव्यक्ति मौजूदा समय के लिए ही नहीं, भविष्य में भी आतंकवादी गतिविधियों के प्रति भारत की सख्ती को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करने वाली रही। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने प्रभावी ढंग से अपने देश की रणनीति और कार्रवाई को दुनियाभर के लोगों को समझाया। रेखांकित करने योग्य पक्ष यह भी है कि देश में सरकार का मुखर विरोध करने वाले नेताओं ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर एक सहयोगी भाव के साथ रखा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से बताते हुए सभी की बातों में भारतीयता की सोच साफ नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर से जुड़े विवादित पक्ष को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीजफायर के लिए अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर था, भारत पर नहीं, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी द्वारा भारत की राष्ट्रभाषा को 'विविधता में एकता' की भाषा बताना भी रहा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के शशि थरूर और बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कही गई बातों की तो वैश्विक स्तर पर खूब चर्चा भी हुई। पाकिस्तान के सहयोग से पल रहे आतंकवाद को वैश्विक मंच पर उजागर करने का यह कदम सचमुच सार्थक संदेश देने वाला रहा।

देश की सुरक्षा और अस्मिता के मोर्चे पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त की गई साझी चिंता देशवासियों को भी भरोसा देने वाली रही। देखा जाए तो यह कूटनीतिक मुहिम वैश्विक मंचों पर पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता को सामने रखने वाला अहम कदम तो थी ही, भविष्य के लिए भी आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत की सोच को स्पष्ट करने में कामयाब रही। बहुत देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। कोलंबिया ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों पर शोक जताने वाला अपना बयान भी वापस लिया। मलेशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर पाकिस्तानी दूतावास ने धर्म की आड़ लेकर अपनी मनवाने की कोशिश की।

मलेशियाई सरकारी अधिकारियों से हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल के सभी 10 कार्यक्रमों को रद करने का यह कहते हुए आग्रह किया कि हम एक इस्लामी देश हैं, आप भी एक इस्लामी देश हैं, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बात न सुनें, मलेशिया में उनके सभी कार्यक्रम रद कर दें। बावजूद इसके मलेशियाई सरकार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों के आयोजन की न केवल मंजूरी दी बल्कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत कर उनका पक्ष भी सुना गया। कोलंबिया की उपविदेश मंत्री वियाविसेंसियो ने भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर के साथ खड़े होकर कहा, "हमें अब इस बात की पूरी जानकारी है कि कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ था।' एक अन्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर लौटीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि 'आतंकवाद के खिलाफ हर देश भारत के साथ पूरी ताकत से खड़ा है।' निःसंदेह, सभी दलों के प्रतिनिधियों का साझा स्वर देश के भीतर आतंकवादी घटनाओं को लेकर जनमानस की भावना समझने से लेकर वैश्विक मोर्चे पर भारत का पक्ष रखने तक, कामयाब कूटनीतिक मुहिम रहा है।

(लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन का मात्र अनुभव करें

संकलित
दर्शन

अकसर हम यह सोचते हैं कि जिसने जीवन में अधिक कठिनाइयों का सामना किया है, वह जल्दी समझदार बन जाता है। कितना सही है यह सोच। वस्तुतः जीवन में कठिन कुछ नहीं होता है। जीवन में सिर्फ परिस्थितियां होती हैं। फिर चाहे आप उसका अनुभव एक कठिनाई के रूप में करें या आनंद के रूप में। यह चुनने का अधिकार आपका अपना है। अगर आप समझदार हैं तो आप हर परिस्थिति को एक आनंदमय प्रक्रिया में बदल देंगे। अगर आप समझदार नहीं हैं, तो आप अपने लिए हर परिस्थिति को कठिनाई बना लेंगे। अगर आप जानते हैं कि अपने दिमाग में चल रही बेतुकी बातों को कैसे महत्व ना दें, अगर आप अपने दिमाग में चल रहे मनोवैज्ञानिक बकवास में उलझे नहीं, तो आप निश्चित रूप से जल्दी समझदार बन जाएंगे।जीवन सिर्फ परिस्थिति है। 'दुखद' परिस्थिति या 'सुखद' परिस्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप आसान परिस्थिति चाहते हैं, तो यह बहुत आसान है। हम आपको एक पिंजरे में बंद कर सकते हैं और जितना आप खा सकते हैं, उससे अधिक भोजन आपको दे सकते हैं। आप बस पिंजरे में रहिए। हम इसका खयाल रखेंगे कि आप सभी चीजों से पूरी तरह सुरक्षित हों। कोई खतरा नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आपको परिवार, बीवी-बच्चों का खयाल नहीं रखना है, रोजी-रोटी नहीं कमानी, कुछ नहीं करना है। कोई भी परेशानी नहीं। सारी बातों का खयाल रखा जाएगा। आप बस उस पिंजरे में रहिए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या इससे आपको सुख मिलेगा? नहीं।

जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे?

संकलित
प्रेरणा

एक मछलीमार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई तो वह सोचने लगा... कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहां कोई मछली ही न हो! उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत-सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं! एक राहगीर ने जब यह नजारा देखा तो उससे कहा- लगता है भैया, यहां पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो! अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछलीमार ने हैरत से पूछा- क्यों, ऐसा क्या है यहां? राहगीर बोला- पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होने यहां मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनतीं। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यहीं होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। क्योंकि यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इन्द्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो.. इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेवें बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी।

अंतर्मन

आज की पाती

हमारे जमीर में घुला जहर

मिलावट अब केवल खाने-पीने तक सीमित नहीं रही, यह हमारे सोच, संबंध और व्यवस्था तक मे घुल चुकी है। मूंगफली मे पत्थर हो या दूध मे डिटर्जेंट, यह मुनाफाखोरी की संस्कृति का विस्तार है। उपभोक्ता की चुप्पी, सरकार की ढील और समाज की 'चलता है' मानसिकता ने इसे स्वीकार्य बना दिया है। मिलावट एक नैतिक संकट है, जो धीरे-धीरे शरीर ही नही, आत्मा को भी बीमार कर रहा है। जब तक ईमानदारी को समर्थन और सच्चाई को स्पेस नही मिलेगा, तब तक हर दाना शक के दायरे मे रहेगा और हर निवाला जहर जैसा लगेगा। आज जो सबसे बड़ी मिलावट हो रही है, वह हमारी सोच, जमीर और व्यवस्था मे हो रही है। हर उत्पाद के साथ-साथ संवेदनाएं, ईमानदारी व नैतिकता भी प्रदूषित हो रही हैं। - राजेंद्र ठाकुर, कवर्धा

करंट अफेयर

सिंगापुर ने साइबर अपराध से जुड़े 1,000 आईपी हटाए

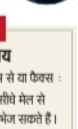

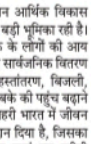

सिंगापुर के अधिकारियों ने 1,000 से अधिक इंटरनेट प्रोटोकॉल (या आईपी) पते को हटा दिया है, जिनके बारे मे माना जाता है कि वे साइबर अपराधों से जुड़े थे । अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) के आपराधिक जांच विभाग के तहत साइबर अपराध कमान के अधिकारियों ने देश में आईपी पते को हटाने के लिए सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के साथ काम किया। यह वैश्विक पुलिस संगठन इंटरपोल के नेतृत्व मे 26 देशों मे चार महीने के अभियान का हिस्सा था और इसे 'ऑपरेशन सिक्योर' नाम दिया गया था। साइबर अपराधियों के खिलाफ यह अभियान इस साल जनवरी से अप्रैल तक चलाया गया। 26 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलकर भौतिक सर्वरों का पता लगाया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 'इन्फोस्टीलर्स' के रूप में जाने जाने वाले दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (मैलवेयर) को बनाए रखते हैं। इस अभियान में भौतिक नेटवर्कों की मैपिंग और लक्षित टेकडाउन को अंजाम देना शामिल था। बयान में कहा गया है कि वैश्विक प्रयास के कारण 20,000 से अधिक दुर्भावनापूर्ण आईपी पते और डोमेन को हटाया गया।

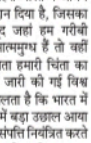

ऑफ बीट

ब्रह्माण्ड का केंद्र आप नहीं पा सकते हैं

पृथ्वी पर, 'विस्तार' का मतलब है कि कुछ बड़ा हो रहा है। और ब्रह्मांड के संबंध मे, यह सच है, कुछ हद तक। विस्तार का मतलब यह भी हो सकता है कि ''सब कुछ हमसे दूर होता जा रहा है', जो ब्रह्मांड के संबंध मे भी सच है। दूर स्थित आकाशगंगाओं पर दूरबीन घुमाएं तो वे सभी हमसे दूर जाती हुई प्रतीत होंगी। इसके अलावा, वे जितनी दूर होती हैं, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। वे आकाशगंगाएँ एक-दूसरे से दूर होती हुई भी दिखाई देती है। इसलिए यह कहना अधिक सटीक होगा कि ब्रह्मांड मे हर चीज एक साथ हर चीज से दूर होती जा रही है। यह विचार सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण है। इसलिए यह पूछना कि ब्रह्मांड का केंद्र कहां है, कुछ हद तक यह पूछने जैसा है कि गुब्बारे की सतह का केंद्र कहां है? ऐसा कोई केंद्र नहीं है। आप गुब्बारे की सतह पर किसी भी दिशा मे, जितनी देर चाहें, यात्रा कर सकते हैं, और आप कभी भी ऐसी जगह पर नहीं पहुंचेंगे जिसे आप इसका केंद्र कह सकें क्योंकि आप वास्तव मे सतह से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। इसी तरह, आप ब्रह्मांड मे किसी भी दिशा मे यात्रा कर सकते हैं और कभी भी उसका केन्द्र नहीं पा सकेंगे, क्योंकि गुब्बारे की सतह की तरह, इसका भी कोई केन्द्र नहीं है।

ट्रेंड

साझा मूल्यों पर चर्चा

आज सुबह ब्रसेल्स मे यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेटसोला के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। भारत-यूरोपीय संघ संसदीय संबंधों को और मजबूत बनाने, लोकतंत्र एवं बहुलवाद के हमारे साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

- एस जयशंकर, विदेश मंत्री

हिंदी सीखने का भी महत्व

तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम हमारी मूल भाषाएं है और हमें उन्हें सीखना चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं। लेकिन इसके अलावा हिंदी सीखने का भी महत्व है। यह हमारे युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान कर सकती है।

- एन चंद्रबाबू नायडू, सीएम, आंध्रप्रदेश

पायलट को श्रद्धांजलि

जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़-लिख कर उन पदों पर पहुंचेंगे जहां से इस देश की नीतियां बनती है, तभी भारत का सही मायनों में विकास होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, किसानों के हितैषी, राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।

- मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

मोदी सरकार की साजिश

मोदी सरकार के 11 साल दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमान, हिंसा और भेदभाव से भरे रहे है। इन्हें संस्थागत रूप से दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और मुख्यधारा से दूर रखने की साजिश जारी है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर मे पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।